नई दिल्ली
28 जून, 2026 रविवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 88

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

टी20 ब्लास्ट 2026 के लिए घरेलू खिलाड़ी के तौर पर नॉट्स आउटलाज टीम में खेलेंगे मोहम्मद आमिर 07

संक्षिप्त वार्ता

सेशेल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी

वेब वार्ता, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सेशेल्स यात्रा पर रवाना हो गए। पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 29 जून तक चलने वाले इस दौरे को भारत की हिंद महासागर नीति, समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष संदेश जारी कर इस दौरे के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह सेशेल्स के राष्ट्रपति पेट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। इस दौरान वह सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और वह भारत के विजन महासागर तथा ग्लोबल साउथ की साझी प्रतिबद्धताओं का अहम भागीदार है। विजन महासागर का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, विकास, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

भारत आ रहीं जापान की पीएम

वेब वार्ता, नई दिल्ली

जापान की पीएम साने ताकाइची तीन दिवसीय दौरे पर भारत आ रही हैं। पीएम ताकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। पीएम ताकाइची

1-3 जुलाई तक नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। यह समिट दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने और मजबूत करने के साथ-साथ परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर देगा। यह जापानी पीएम ताकाइची का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी अगस्त 2025 में जापान के दौरे पर गए थे, जहां वे 15वें भारत-जापान सालाना समिट में शामिल हुए। यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में 28 से 30 जून तक पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

वेब वार्ता, जबलपुर

पल्स पोलियो अभियान के तहत जबलपुर रेल मंडल ने 28 से 30 जून तक प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं चयनित ट्रेनों में पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे चिकित्सा विभाग, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स तथा सेंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड की संयुक्त टीम जबलपुर, मदन महल, कटनी, सतना, रीवा, सागर, नरसिंहपुर, पिपरिया सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष बूथ संचालित करेगी। रेल प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान भी अपने बच्चों को पोलियो की दो बूंद जीवनरक्षक खुराक अवश्य पिलाएं।

प्रशांत महासागर में डबल तूफान

10 लाख लोगों की जान सांसत में

प्रशांत महासागर में उठे दो भयानक चक्रवाती तूफानों - मेक्खला और हिगोस ने ताइवान और जापान में कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे करीब 10 लाख से अधिक लोगों की सांसें हलक में अटकी हुई हैं।

वेब वार्ता, टोक्यो

तूफान मेक्खला, जो अब कमजोर होकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल गया है, में अभी भी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचाने की क्षमता है। इसके साथ ही एक और तूफान हिगोस भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोहरे चक्रवाती सिस्टम का पहला प्रहार ताइवान पर हुआ है, जहां दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने ऐसी बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दिया है कि पूरा द्वीप पानी-पानी हो गया है। ताइवान के दक्षिणी बंदरगाह शहर काऊशुंग में बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने से एक 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई।

वहीं, ह्सिनचू काउंटी में बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुकी एक कार के भीतर से 49 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया है, जबकि इसी इलाके में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने खेत पर जाते समय बाढ़ के पानी में लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। ताइवान के पहाड़ी इलाकों में मलबे के बहाव की गंभीर चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि मौसम एजेंसी के अनुसार, गुरुवार से अब तक कई इलाकों में 88 सेंटीमीटर (34.6 इंच) तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जा चुकी है। ताइवान को प्रभावित करने के बाद, यह तूफान जापान के मुख्य द्वीपों क्यूशू, शिकोकू और होनशू की तरफ मुड़ गया है, जिससे टोक्यो, ओसाका और नागोया जैसे घनी आबादी वाले शहर सीधे खतरे की जद में आ गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तूफान मेक्खला प्रशांत महासागर में आगे बढ़ रहे एक अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान हिगोस के साथ टकराने वाला है। मौसम विज्ञान में इस दुर्लभ वायुमंडलीय घटना को फुजीवाड़ा इफेक्ट कहा जाता है, जहां दो तूफान आपस में भिड़ते हैं, तो उनकी ताकत और दिशा का सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे तबाही का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

घर खाली करने और शिविरों में जाने को कहा

इस गंभीर खतरे को देखते हुए, जापान की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने आपातकालीन कदम उठाते हुए 10 लाख से अधिक निवासियों को तुरंत अपने घर खाली करने और सुरक्षित शिविरों में जाने की सख्त सलाह जारी की है। सरकारी प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपदा स्तर की मूसलाधार बारिश का खतरा बना हुआ है। अब तक दक्षिणी क्षेत्र कागोशिमा में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने और तीन लोगों को मामूली चोटें आने की रिपोर्ट मिली है, जबकि दर्जनों इमारतें जलमग्न हो चुकी हैं। तूफान के चलते जापान का परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से चरमरा गया है।

जापान ने 120 उड़ाने की रद्द

जापान एयरलाइंस और ऑल निप्पॉन एयरवेज ने ओकिनावा और कागोशिमा जाने और वहां से आने वाली कुल 120 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण ट्रेन रूटों को भी रोक दिया गया है। औद्योगिक मोर्चे पर, मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों के बंद होने की वजह से दिग्गज ऑटोमेकर कंपनी टोयोटा ने क्यूशू स्थित अपने विनिर्माण प्लांट में परिचालन पूरी तरह से निलंबित कर दिया है, जबकि निसान ने भी अपनी कुछ मुख्य प्रोडक्शन लाइनों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। क्योटो और ओसाका के अधिकारियों ने नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर बाढ़ की चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने को कहा है, क्योंकि यह दोहरा खतरा लाखों लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है।

देश में मानसून का नया मिजाज

मप्र तरबतर, यूपी-बिहार में आंधी, दिल्ली को इंतजार

वेब वार्ता, नई दिल्ली

मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कुल 16 राज्यों के लिए बारिश और तेज हवाओं का व्यापक अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में मानसून की एंट्री उम्मीद से थोड़ी देर से हो रही है। पहले अनुमान था कि 27 जून तक मानसून राजधानी पहुंच जाएगा। लेकिन अब आईएमडी का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक इसके पहुंचने की संभावना है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा। 27 जून से 1 जुलाई के बीच प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। गरज-चमक, हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। 28 जून से तापमान में गिरावट महसूस होग। 30 जून और 1 जुलाई को बारिश की संभावना और मजबूत बताई गई है। ऐसे में दिल्लीवालों को फिलहाल झमाझम बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।

यूपी में 29 से बदलेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में अभी दो दिन तक कई जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है, लेकिन 29 जून से तस्वीर तेजी से बदलने के संकेत हैं। लखनऊ, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, बरेली, हाथरस, मऊ, बलिया और औरैया समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार 29 जून से 1 जुलाई के बीच तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने और आंधी की भी आशंका है।

रेगिस्तान में होगी झमाझम बारिश

राजस्थान में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है. जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, टोंक, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 27 से 29 जून के बीच अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी।

पंजाब-हरियाणा में हुई लू की विदाई

पंजाब और हरियाणा में पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, लेकिन अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में नया मौसमी सिस्टम सक्रिय होगा, इससे दोनों राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होंगी।

मप्र में सबसे ज्यादा मेहरबान रहेगा मानसून

अगर किसी राज्य पर मानसून सबसे ज्यादा मेहरबान दिख रहा है तो वह मध्य प्रदेश है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, धार, देवास, रतलाम, शाजापुर और बालाघाट समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। कई जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। लगातार बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट आएगी और किसानों को खरीफ की बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी।

पहाड़ों में आंधी, ओले और बारिश

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं देहरादून में तापमान में गिरावट के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। यात्रियों और चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर में मध्यम बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

5 साल में विकास अनिवार्य, नहीं तो परमिशन कैंसिल

मध्य प्रदेश कालोनी अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार

वेब वार्ता, भोपाल

मध्य प्रदेश में अवैध और अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कालोनी अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के पास भेजा जाएगा। इस नए कानून के लागू होने से मध्य प्रदेश में न सिर्फ अवैध कालोनी काटने वालों पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत अवैध कालोनियों की परिभाषा को भी पूरी तरह बदल दिया गया है।

नए ड्राफ्ट के अनुसार अब किसी भी कालोनाइजर को कालोनी काटने के 5 साल के भीतर वहां सडक, पानी, बिजली, सीवेज समेत सभी आंतरिक विकास कार्य पूरे कराने होंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में नगर निगम और टीएनसीपी से कालोनाइजर को 2 वर्ष तक का अतिरिक्त समय मिल सकता है। अगर कालोनाइजर अनुमति लेने के बाद भी एक साल के अंदर कालोनी नहीं काटता है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नए अधिनियम में अवैध कालोनी की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया है। अब शासकीय भूमि, प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, निकायों की जमीन, विकास योजना, खेल-पार्क, पुरातत्व, सांस्कृतिक विरासत, नदी-नालों और राष्ट्रीय या राज्य मार्गों के लिए अधिसूचित जमीन पर बनाई गई कालोनियों को अवैध माना जाएगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 वर्ष तक की सजा और 5 करोड़ रुपए तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह एक्ट भोपाल, महू, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के सभी सातों कैंटोनमेंट क्षेत्रों में भी लागू होगा।

अनाधिकृत कालोनियों में मकान लेना होगा महंगा

यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत कालोनी में मकान या प्लाट खरीदता है, तो उसे यह सौदा बेहद महंगा पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रों में आंतरिक विकास कार्यों की 50 प्रतिशत राशि वहां के रहवासियों को खुद देनी होगी। बाकी की 50 प्रतिशत राशि कालोनाइजर की बैंक राशि और प्रॉपर्टी को जब्त कर वसूली जाएगी। इसके अलावा शहर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और विमानतल के पास के क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी।

अफसरों की तय होगी जवाबदेही

अवैध कालोनियों को रोकने के लिए शहरों में वार्ड प्रभारियों से लेकर कलेक्टर तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं शिकायत मिलने पर यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरेगी। अवैध और अनाधिकृत कालोनियों को हटाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिसके बाद सरकार सीधे एक्शन लेगी। वहीं वैध कालोनाइजरों को तमाम अनुमतियां देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

खड़ी कार का एयरबैग खुलने से युवक की मौत

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक खड़ी कार में अचानक एयरबैग खुलने से 25 साल के कार डीलर की मौत हो गई। युवक का नाम मोहित सोनी है। वह एक 15 साल पुरानी कार के अंदर बैठा था। तभी अचानक गाड़ी का सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो गया। एयरबैग इतनी तेजी से खुला कि उसके जोरदार झटके से उसकों गंभीर चोटें आईं। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई।

अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप

जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस हुए झटके

शनिवार शाम 7:05 बजे अफगानिस्तान के कालाफगन से करीब 81 किलोमीटर दूर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा के पास था। इसकी गहराई 192 किलोमीटर दर्ज की गई, जिसके कारण इसके झटके दूर-दूर तक महसूस किए गए।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान तक देखा गया। भारत में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोगों ने धरती में कंपन महसूस किया।

घरों से बाहर निकले लोग

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामुला, कुपवाड़ा और जम्मू सहित कई इलाकों में हल्के से मध्यम झटके महसूस होने के बाद लोग एहतियातन घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। वहीं, दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम में भी कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए।

अभी नुकसान की जानकारी नहीं

फिलहाल जम्मू-कश्मीर या देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एआई से आसान होगा टैक्स और जीएसटी संबधी काम?

वेब वार्ता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष सम्मेलन में देशभर से आए लगभग 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कर व्यवस्था, जीएसटी अनुपालन और वित्तीय ऑडिट में एआई की बढ़ती भूमिका पर व्यापक चर्चा की गई।

दिल्ली-रांची इंडिगो फ्लाइट में बंद हुआ एसी, गर्मी से भड़के 170 यात्री

वेब वार्ता, नई दिल्ली

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को उस समय एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जब रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में उड़ान भरने से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। विमान संख्या 6ई 2614 रनवे तक पहुंच चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर आई इस खराबी के कारण पायलट को विमान को वापस मोड़ना पड़ा। यह घटना उस समय और भी गंभीर हो गई जब तकनीकी खराबी के कारण विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया, जिससे दिल्ली की भीषण गर्मी और उमस भरे माहौल में यात्रियों का दम घुटने लगा। इस अप्रत्याशित स्थिति ने 170 यात्रियों को दो घंटे तक विमान के अंदर ही कैद कर लिया, जिससे उन्हें अकल्पनीय परेशानी का सामना करना पड़ा।

2 घंटे तक बंद रख केबिन का दरवाजा

रनवे से लौटने के बाद तकनीकी खराबी की वजह से विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। बेहद चिंताजनक बात यह रही कि विमान के अंदर बैठे 170 यात्रियों को बाहर निकालने के बजाय, केबिन का दरवाजा करीब 2 घंटे तक बंद रखा गया। दिल्ली की भीषण गर्मी और उमस के बीच एसी बंद होने से विमान के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया और केबिन किसी भट्टी की तरह तपने लगा। ताजी हवा न मिलने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सांस लेने के लिए तड़पने लगे और यात्रियों की हालत बेहाल हो गई। कई यात्री पसीने से तरबतर हो गए और उन्हें घुटन महसूस होने लगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ गया।

संपादकीय

भारतीय साबित करो

क्या हम, आप और देश के करोड़ों लोग भारतीय हैं? क्यों यह सवाल क्यों उठना चाहिए? यकीनन हम भारतीय हैं, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर आप को कहा जाए कि भारतीयता साबित करो, तो आप क्या करेंगे? असमर्थ और असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि यह बेहद पेचीदा मामला बन गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट महज एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है। यह व्यवस्था 1967 से जारी है, जब पासपोर्ट कानून बनाया गया था। सर्वोच्च अदालत भी 2006 और 2013 में दो महत्वपूर्ण फैसले सुना चुकी है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है। 2013 में ही बंबई उच्च न्यायालय भी ऐसा ही फैसला सुना चुका है। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने भी उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया चूंकि विशेष परिस्थितियों में पासपोर्ट गैर-भारतीय को भी जारी किया जाता रहा है, लिहाजा इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सवाल है कि पासपोर्ट के कवर पर भारतीय गणराज्य अंकित होता है और शेष विश्व में उस दस्तावेज का धारक भारतीय माना जाता है। उसकी पहचान भारतीय के तौर पर होती है। फिर पासपोर्ट नागरिकता का आधार क्यों नहीं है? गैर-भारतीय के पासपोर्ट पर उसकी नागरिकता का उल्लेख किया जाता है। बहरहाल पासपोर्ट की बहस यहीं रोक देते हैं, लेकिन करीब 134 करोड़ देशवासियों के पास आधार कार्ड हैं। 97 करोड़ से अधिक देशवासियों को मतदाता पहचानपत्र जारी किए गए हैं। देश का नागरिक ही मतदाता बन सकता है, लिहाजा मतदाता पहचानपत्र परोक्ष रूप से नागरिकता की पुष्टि करता है। करोड़ों भारतीयों के पास राशन कार्ड, पैनकार्ड, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज और जन्म प्रमाणपत्र हैं। ये तमाम दस्तावेज सरकारी हैं और सरकारी विभागों ने ही जारी किए हैं। इन्हीं के आधार पर सरकारें 81.35 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन हर माह बांटती हैं। क्या विदेशियों को यह राशन बांटा जा रहा है?

बहरहाल आधार कार्ड की मांग सर्वाधिक है, क्योंकि यह धारक की पहचान का प्रमाणपत्र है, लेकिन सरकार इसे भी नागरिकता का आधार नहीं मानती। आधार कार्ड धारक की पहचान के मायने क्या हैं? धारक का नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, संपर्क-सूत्र और बेहद संवेदनशील बॉयोमीट्रिक डाटा इस कार्ड में निहित है। ऐसी पहचान का व्यक्ति भारतीय क्यों नहीं है? आश्चर्य है मोदी सरकार की इन व्यवस्थाओं पर..! आखिर इतने सरकारी कार्ड, दस्तावेजों का औचित्य क्या है? खत्म करो इन्हें। गंभीर और संवेदनशील सवाल है कि औसत भारतीय अपनी नागरिकता किस आधार पर साबित करे? यदि मोदी सरकार देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन(एनआरसी) की व्यवस्था लागू करना चाहती है और उसे मानक नागरिकता दस्तावेज की मान्यता देना चाहती है, तो स्पष्ट करे। बहानों और बेजा दलीलों की आड़ में छिप कर 147 करोड़ से अधिक भारतीयों की नागरिकता पर सवाल उठाना न तो राष्ट्रवाद है और न ही देशहित में है। एनआरसी की व्यवस्था 1952 से शुरू की गई थी, संविधान में भी प्रावधान है, लेकिन आज तक यह व्यवस्था देश भर में लागू नहीं हो सकी। राजनीतिक तौर पर एक विशेष समुदाय को डराया जरूर जाता रहा है। असम में यह प्रयोग फ्लॉप रहा। वहां मुसलमान कम और ज्यादा बंगाली हिंदू निकले। असमंजस रहा कि किसे एनआरसी की आड़ में देश के बाहर खदेड़ा जाए, लिहाजा प्रयोग वहीं बंद कर दिया गया। नागरिकता कानून भी 1955 का है, लेकिन उसमें भी 2003, 2015, 2019 और 2025 में संशोधन किए गए। तमाम संशोधन भाजपा-एनडीए की सरकार के दौरान किए गए। इसके बावजूद सरकार नागरिकता के मानक आधार तय नहीं कर पाई। दलीलें दी जाती रही हैं कि दस्तावेज फर्जी, नकली भी बनते रहे हैं। यह सरकार के लिए लानत, अक्षमता, शर्मिन्दगी का मामला है कि सरकार आजादी के 79 साल के बाद भी नागरिक और घुसपैठिए में अंतर नहीं कर पाई है। जो भारतीय बीते 45 साल से मतदान करता रहा है, जन्म के बाद उम्र के 70 साल भी भारत की मिट्टी और फिजाओं में जिए हैं, उससे भी चुनाव आयोग प्रमाण मांग रहा है। दशकों पहले दिवंगत हुए माता-पिता के भारतीय दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। क्या यह संभव है? हम किस देश में बसे हैं, यह भी अनिश्चित, अप्रमाणित है। सरकार को इस संबंध में अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए।

भरोसे के रिश्तों के कत्ल से कांपता समाज

पुणे के लोहगढ़ किले की ऊंची पहाड़ी से मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने के आरोप में सिया गोयल की गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इससे पहले मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान कथित तौर पर पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर की गई हत्या की घटना ने भी समाज को स्तब्ध किया था। ये घटनाएं केवल अपराध की श्रेणी में रखकर भुला देने योग्य नहीं हैं। ये उन मूल्यों, विश्वासों और रिश्तों की बुनियाद पर गहरा आघात हैं, जिन पर भारतीय समाज सदियों से खड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन-दृष्टियों का मिलन माना गया है। विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा गया है। ऐसे में यदि कोई पति, पत्नी, मंगेतर या प्रेमी एक-दूसरे को जीवन का साथी मानने के बजाय बाधा और कांटा समझने लगे, तो यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के संकट का संकेत है।

राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल जैसे मामलों में सबसे अधिक विचलित करने वाला पक्ष यह है कि हत्याएं उन लोगों ने कीं, जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया गया था। विश्वास का यह टूटना ही समाज को भयभीत करता है। किसी भी सभ्यता की शक्ति उसकी सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में निहित भरोसा होता है। जब यह भरोसा टूटने लगता है, तब समाज भीतर से कमजोर होने लगता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कोई युवती या युवक किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है, तो क्या उसके सामने ह्यनाह्व कहने का विकल्प नहीं था? आधुनिक समाज ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पर्याप्त स्थान दिया है। सगाई तोड़ना, विवाह से इनकार करना, आपसी सहमति से अलग होना-ये सभी वैधानिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध हैं। फिर हत्या जैसी भयावह मानसिकता क्यों जन्म ले रही है?

इस प्रश्न का उत्तर केवल कानून या पुलिस के पास नहीं है। इसके लिए समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, धमार्चार्यों और परिवार संस्थाओं को मिलकर मंथन करना होगा। आज का युवा एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां पारंपरिक मूल्य और आधुनिक जीवनशैली के बीच गहरा द्वंद्व मौजूद है। एक ओर परिवार की अपेक्षाएं हैं, दूसरी ओर व्यक्तिगत इच्छाएं। संवाद के अभाव में यह द्वंद्व कई बार मानसिक तनाव, विद्रोह और हिंसा का रूप ले लेता है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड, निक्की यादव हत्याकांड, बेंगलुरु, दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रेम-संबंधों से जुड़े अनेक जघन्य अपराध देखे हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि प्रेम, विवाह और संबंधों को लेकर समाज में गहरी अस्थिरता एवं अविश्वास बढ़ रहा है। यह अस्थिरता केवल स्त्री या पुरुष तक सीमित नहीं है, दोनों पक्षों में हिंसक प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। मोबाइल संस्कृति और डिजिटल संसार ने इस संकट को और जटिल बनाया है। मोबाइल फोन, जो कभी दूरियों को समाप्त करने का माध्यम था, आज अनेक मामलों में षडयंत्र, छल और अपराध का साधन बनता जा रहा है। सोशल मीडिया ने तुलना, उपभोगवाद, त्वरित सुख और आभासी संबंधों को बढ़ावा दिया है। डिजिटल दुनिया में बने रिश्ते कई बार वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों और मयार्दाओं से कटे होते हैं। परिणामस्वरूप धैर्य, सहनशीलता और त्याग जैसी पारिवारिक जीवन की आवश्यक विशेषताएं कमजोर पड़ रही हैं। एक अन्य गंभीर पक्ष सांप्रदायिक अविश्वास और तथाकथित ह्यलव जिहादह्व जैसे विवादों के संदर्भ में भी सामने आता है। जब प्रेम, विवाह या संबंधों का उपयोग छल, पहचान छिपाने, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक शोषण अथवा भावनात्मक उत्पीड़न के लिए किया जाता है, तब केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समुदायों के बीच विश्वास का भी हनन होता है। यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के संबंध पारदर्शिता, स्वेच्छा, समानता और ईमानदारी पर आधारित हों। पहचान छिपाकर, धोखे से अथवा किसी वैचारिक एजेंडे के तहत बनाए गए संबंध सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण भी आवश्यक है। कुछ घटनाओं के आधार पर किसी सम्पूर्ण समुदाय को दोषी ठहराना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए भी घातक है। भारत की शक्ति उसकी विविधता और सांप्रदायिक सौहार्द में निहित है। सदियों से विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग यहां पारस्परिक सम्मान और विश्वास के आधार पर साथ रहते आए हैं। अतः किसी भी अपराध को अपराधी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए, न कि पूरे समुदाय की पहचान के रूप में। हमें प्रेम के नाम पर छल का विरोध करना चाहिए, लेकिन साथ ही सामाजिक सौहार्द और मानवीय एकता को भी अक्षुण्ण रखना होगा। आज सबसे बड़ी चुनौती परिवार संस्था को पुनः सशक्त बनाने की है। संयुक्त परिवारों के विघटन, महानगरीय जीवन, एकाकीपन और अत्यधिक व्यस्तता ने परिवार के भीतर संवाद को कम कर दिया है। माता-पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता बढ़ रही है। बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा और मूल्यपरक संस्कार कम होते जा रहे हैं।

विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में केवल रोजगारपरक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। वहां जीवन-कौशल, नैतिक शिक्षा, भावनात्मक संतुलन, संबंध प्रबंधन और पारिवारिक मूल्यों पर भी गंभीर कार्य होना चाहिए। युवा पीढ़ी को यह समझाना होगा कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं-उत्तरदायित्व है, संबंध का अर्थ उपभोग नहीं-समर्पण है और मतभेद का समाधान हिंसा नहीं-संवाद है। धर्म और आध्यात्मिक संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी धर्म प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा और सह-अस्तित्व का संदेश देते हैं। यदि धार्मिक संस्थाएं युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों, आत्मसंयम और संवाद की संस्कृति से जोड़ें, तो अनेक सामाजिक विकृतियों को रोका जा सकता है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों ने सदैव चरित्र, नैतिकता और आत्मानुशासन को समाज की आधारशिला माना।

पुणे और मेघालय की घटनाओं ने हमें चेतावनी दी है कि यदि हम अभी नहीं चेते, तो रिश्तों का संकट और गहरा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार, समाज और राष्ट्र-तीनों स्तरों पर विश्वास की पुनर्स्थापना का अभियान चलाएं। परिवारों में संवाद बढ़े, युवाओं को निर्णय की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का बोध कराया जाए, डिजिटल संस्कृति पर संयम हो और सामाजिक-सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाया जाए। सभ्यता की पहचान ऊंची इमारतों, तकनीकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि से नहीं होतीय उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहां लोग एक-दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। यदि भरोसा टूट गया, तो समाज की आत्मा घायल हो जाएगी। इसलिए आज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दायित्व है-रिश्तों के भरोसे को बचाना, मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित करना और प्रेम, विश्वास तथा सौहार्द की उस परंपरा को मजबूत करना, जिसने भारतीय समाज को सदियों से जीवंत बनाए रखा है।

आज भारतीय समाज जिस संक्रमणकाल से गुजर रहा है, उसमें रिश्तों का संकट केवल पति-पत्नी अथवा प्रेम-संबंधों तक सीमित नहीं रह गया है। एक ओर पुणे और मेघालय जैसी घटनाएं भरोसे के रिश्तों की हत्या कर रही हैं, तो दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही के कारण अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर आगजनी एवं दुर्घटनाओं में मासूमों की मौतें व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को तोड़ रही हैं। सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक कट्टरता, पहचान छिपाकर बनाए जाने वाले संबंध, प्रेम के नाम पर छल और शोषण जैसी घटनाएं भी सामाजिक सौहार्द की नींव को कमजोर कर रही हैं। भौतिकता, उपभोक्तावाद और अंधी प्रतिस्पर्धा की आंधी ने संयम, सादगी, त्याग और पारिवारिक मयार्दाओं जैसे जीवन-मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया है। वहीं नशे का बढ़ता प्रचलन, शराब और मादक पदार्थों की लत युवा पीढ़ी को परिवार और समाज से काटकर हिंसा, अपराध और संवेदनहीनता की ओर ले जा रही है। जब समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थ, वासना और तात्कालिक सुख को ही सर्वोच्च मानने लगे, तब रिश्ते साधना नहीं, सौदे बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि परिवार, शिक्षा, धर्म, मीडिया और शासन-सभी मिलकर मानवीय मूल्यों, पारदर्शिता, संवाद, नैतिकता और पारस्परिक सम्मान की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। क्योंकि यदि मानवीय रिश्तों की बुनियाद ही हिल गई, तो न केवल परिवार टूटेंगे, बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सभ्यता का पूरा ढांचा भी संकट में पड़ जाएगा।

लेखक- ललित गर्ग

पासपोर्ट, एसआईआर, नागरिकता, मतदाता और चुनाव आयोग?

25 जून से पंजाब सहित कई राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो गया है। 24 जून को विदेश मंत्रालय द्वारा यह कहा गया, पासपोर्ट नागरिकता का वेध दस्तावेज नहीं है। पंजाब के नागरिकों के पास सबसे ज्यादा पासपोर्ट हैं। पंजाब के नागरिक बड़ी संख्या में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य देशों में एनआरआई के रूप में रह रहे हैं। पंजाब में हर घर में पासपोर्ट एक प्रमाणित दस्तावेज है। एसआईआर के ठीक पहले विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद पंजाब और अन्य राज्यों में नागरिकता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब लोग सरकार से पूछ रहे हैं, ऐसा कोई दस्तावेज बताएं, जो नागरिकता का प्रमाण हो। इस विवाद के शुरू होते ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की जा रही है, उसमें पासपोर्ट को भी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चुनाव आयोग इसके साथ और कौन-कौन से दस्तावेज मांगता है। यह या तो चुनाव आयोग जानता है, या भगवान जानते हैं। जैसा पश्चिम बंगाल की एसआईआर के समय चुनाव आयोग द्वारा बिहार एवं अन्य राज्यों की तुलना में अन्य नियम लागू किये। लगभग 1 करोड़ मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया। चुनाव आयोग जो कहता है, वह करता नहीं है, पश्चिम बंगाल में यही हुआ। यह लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी गई। कहीं से कोई न्याय मतदाताओं को नहीं मिला। उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिन 27 लाख मतदाताओं ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, मतदान के पहले यदि उसका निराकरण नहीं होता है, तो अगली बार मतदान कर लेना। ऐसे लाखों मतदाताओं का मतदान का संवैधानिक अधिकार छिन गया।

अभी तक एसआईआर के माध्यम से लगभग 6.50 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग हो चुके हैं। अब जिन राज्यों में चुनाव होना है। चुनाव के ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करना एक बार फिर विवादों में है। पंजाब में अभी तक भाजपा की सरकार नहीं बनी है। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार कभी नहीं बनी थी। अब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। अब भाजपा ने पंजाब को अपने निशाने पर लिया है? इस तरह के आरोप सामने आने लगे हैं। 2017 के बाद से चुनाव आयोग में बहुत पानी बह गया है। दर्जनो सॉफ्टवेयरौं का उपयोग, चुनाव के लिए आयोग द्वारा शुरू किया गया है। उसके बारे में राजनीतिक दलों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। हर बार नए-नए सॉफ्टवेयर का उपयोग चुनाव आयोग करता है। चुनाव की निष्पक्षता को लेकर पिछले 5 वर्षों से तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। मतदान से ज्यादा वोटो की गिनती हो जाती है। ईवीएम मशीन, बीवीपेट और कंट्रोल पैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाओं के माध्यम से जो मामले चल रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, उससे राजनीतिक दलों और मतदाताओं का विश्वास चुनाव आयोग पर कम होता चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम मशीनों के जलने का समाचार आया। 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल वहां चुनाव आयोग ने तैनात कर रखा है। वीडियो फुटेज 45 दिन की समय सीमा के अंदर मांगने के बाद भी नहीं दिए जाते हैं। मतदाता सूची और फार्म 17 की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव के पहले एसआईआर शुरू करता है। चुनाव के कुछ दिन पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं। मतदाताओं को इसकी जानकारी तब मिलती है, जब वह कुछ कर नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मतदाताओं और राजनीतिक दलों में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास बढ़ता जा रहा है।

नागरिकता को लेकर भारत सरकार और चुनाव आयोग यह नहीं बता पा रहा है, कौन सा वह दस्तावेज नागरिकता के लिए मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह नहीं बताया कि भारत में नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य है। चुनाव आयोग और सरकार मिलकर जो निर्णय लेते हैं। न्याय पालिका, चुनाव आयोग को स्वतंत्र निकाय मानकर उस पर ठप्पा लगा देता है। जिसके कारण यह विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। नागरिकता मौलिक अधिकारों में शामिल है। 18 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। मतदाता सूची में कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो, कोई व्यक्ति जो पात्र है, वह मतदान करने से वंचित न हो। 1952 से लेकर 2024 तक चुनाव आयोग के बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण करते थे। मतदाता सूची तैयार करते थे। नागरिकता प्रमाणित करने का चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। फिर भी नागरिकता के नाम पर चुनाव आयोग द्वारा जो खेल खेला जा रहा है उसका सभी जगह विरोध होना शुरू हो गया है। करोड़ों की संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है, जिसके नागरिकों ने आक्रांताओं से लड़कर महिलाओं और बच्चों को बचाने का काम किया। पंजाब इस तरीके की कार्यवाही को कभी स्वीकार नहीं कर पाता है। किसानों का आंदोलन सभी को याद रखना चाहिए। जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। ऐसी स्थिति में केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत सरकार और न्यायपालिका को जिम्मेदारी, निष्पक्षता और मतदाताओं का भरोसा जीतना होगा। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी चुनाव हैं, इस पर विश्वास बना रहे। इसके लिए सजग होने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ, तो आगे चलकर इसके बड़े दुष्परिणाम देश में देखने को मिल सकते हैं।

लेखक- सनत जैन

तुगलकी रास्ते से सत्ता की चाहत का हश्र

देश के दूसरे किसी राज्य में ऐसा तांडव किसी राजनीतिक दल का कभी देखने को नहीं मिला, जैसा शिवसेना ने महाराष्ट्र में दिखाया था। कई दशकों तक शिवसेना की दहशत की यह छाप बनी रही। बाला साहेब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और गद्दी नहीं मिलने के कारण शिवसेना छोड़ कर अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बनाने वाले भतीजे राज ठाकरे ने भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की।

सत्ता नहीं मिलने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मवालियों वाला तरीका अपनाया और इसको नाम दिया मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का। राजनीति चमकाने के लिए मनसे ने भाषा और संस्कृति को मुद्दा बना कर गैरकानूनी हरकतें करने में कसर बाकी नहीं रखी। इसके बावजूद किसी भी तरह के चुनावों में उसे सफलता हासिल नहीं हो सकी। देश के राजनीतिक दलों के लिए शिवसेना और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हश्र सीखने लायक सबक है। राज्य के विकास के बजाय कानून हाथ में लेकर सत्ता कायम करने की चाहत अंततः क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए घातक साबित होगी.

डर और आतंक की राजनीति करने वाली शिवसेना घुटने पर आ चुकी है। नौबत यह आ गई है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की मोदी सरकार को अपनी शर्तों पर नचाने का सपना देखने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ठिकाना छिन गया है। खुद सेना के सांसदों ने ही यह कारनामा कर दिखाया है। पार्टी के पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने से लाचार उद्धव ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर डाली। शिवसेना (यूबीटी) गुट के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना यूबीटी की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट की संख्या 7 से बढकर 13 हो गई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिस महाराष्ट्र में एक दौर में एकीकृत शिवसेना की तूती बोलती थी, वहां उसकी बोलती भी लगभग बंद हो जाएगी। इस हालत के लिए शिवसेना खुद जिम्मेदार है। कायदे-कानून भूल कर हर हालत में सिर्फ ताकत के बलबूते सत्ता पाने का ख्वाब देखने वाली शिवसेना यह भूल गई कि संविधान से इतर जाकर गैर लोकतांत्रिक तौर-तरीकों से सत्ता नहीं मिल सकती। देश के अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरह सिकुड़ती शिवसेना का इतिहास कुछ ज्यादा ही काला रहा है। देश में यदि ममता बनर्जी के बाद किसी ने संविधान और कानून कायदों को ठेंगा दिया है तो वह है शिवसेना। शिवसेना ने भी ममता की तरह अपने ही कायदे कानून चलाने में कसर बाकी नहीं रखी। शिवसेना का ख्याल आते ही, देश के आम जनमानस में महाराष्ट्र में शिवसैनिकों की छवि उभरती थी, हाथों में डंडे या हथियार लिए शिवसैनिक और माथे पर शिवसेना का कपड़ा लपेटे हुए। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के दौरान बनी छवि से यह जाहिर होता था कि किसी को कानून की परवाह नहीं है।

कानून वही है जो शिवसेना बोल दे। किसी ने जरा भी विरोध करने का दुस्साहस किया तो उसकी खैर नहीं। महाराष्ट्र में चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, शिवसेना का आतंक इतना जबरदस्त था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठा सके। बाल ठाकरे ने बाहर से आकर मुंबई बसने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र को सिर्फ मराठियों का कहकर संबोधित किया। खासतौर पर दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध में उन्होंने कई भद्दे नारे भी दिए। शिवसेना का मुखपत्र माने जाने वाले ह्यसामनाह्व समाचार पत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई पलायन करने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बता, बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ सहयोग न करने की सलाह दी। साथ ही इन दो राज्यों से मुंबई बसने वाले नेताओं और अभिनेताओं की भी बाल ठाकरे द्वारा आलोचना की गई। मोहम्मद अफजल की फांसी की सजा पर कोई फैसला न सुनाने के लिए बाल ठाकरे ने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम पर भी अभद्र टिप्पणियां की थी। वैलेंटाइन डे को हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए खतरा बता, दुकानों और होटलों में तोड़-फोड करने के अलावा प्रेमी युगलों पर हमला, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए जनता में बाल ठाकरे के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया। सचिन तेंदुलकर द्वारा भारत की तेजी से विकसित हो रही वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को सभी भारतीयों का शहर बताने पर बाल ठाकरे भडक उठे और उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर ह्यमराठी मानसिकताह्व को ठेस पहुंचा रहे हैं। ठाकरे और तेंदुलकर, जो मूल रूप से मराठी थे, के बीच हुई इस तीखी बहस ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरीं। शिवसेना का ताज नहीं मिलने पर अलग हुए भतीजे राज ठाकरे ने भी बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, किन्तु दाल नहीं गली। संसद सदस्य जया बच्चन भी अपनी कथित ह्यमराठी-विरोधीह्व टिप्पणियों के कारण राष्ट्रीय विवाद में फंस गईं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य और वहां के लोगों का राष्ट्रीय भाषा की आड़ में अपमान करने के लिए जया बच्चन से सार्वजनिक माफी मांगने का आह्वान किया। डर के मारे बच्चन और उनके पति, अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक माफी जारी करते हुए कहा कि वे हिंदी में इसलिए बोले क्योंकि वे उत्तर प्रदेश (उत्तर भारत) से आए थे। मुंबई या महाराष्ट्र में जिसे रहना है और कारोबार चलाना है, उसे शिवसेना की सारी शर्तें पूरी करनी होती थी। शिवसेना के आगे सिर झुकाने वालों में बॉलीवुड के फिल्मी सितारे, उद्योगपति, क्रिकेटर सहित तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल थीं। मीडिया भी शिवसेना के बारे में खबर छापने या टीवी पर दिखाने से पहले कई बार सोचता था। यह सब शिवसैनिकों का खौफ था।

देश के दूसरे किसी राज्य में ऐसा तांडव किसी राजनीतिक दल का कभी देखने को नहीं मिला, जैसा शिवसेना ने महाराष्ट्र में दिखाया था। कई दशकों तक शिवसेना की दहशत की यह छाप बनी रही। बाला साहेब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और गद्दी नहीं मिलने के कारण शिवसेना छोड़ कर अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बनाने वाले भतीजे राज ठाकरे ने भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। सत्ता नहीं मिलने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मवालियों वाला तरीका अपनाया और इसको नाम दिया मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का। राजनीति चमकाने के लिए मनसे ने भाषा और संस्कृति को मुद्दा बना कर गैरकानूनी हरकतें करने में कसर बाकी नहीं रखी। इसके बावजूद किसी भी तरह के चुनावों में उसे सफलता हासिल नहीं हो सकी। देश के राजनीतिक दलों के लिए शिवसेना और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हश्र सीखने लायक सबक है। राज्य के विकास के बजाय कानून हाथ में लेकर सत्ता कायम करने की चाहत अंततः क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए घातक साबित होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पहले माकपा के शासन काल में हिंसा होती रही। इस हिंसा का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आईं, लेकिन हिंसा रुकी नहीं और विरोधी दलों के कार्यकताओं पर हिंसा का तांडव पहले की तरह ही जारी रहा। अब नई सरकार को भी इस सबक को याद रखना होगा।

योगेंद्र योगी, स्वतंत्र लेखक

आलेख

आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज वैध?

भारत में नागरिकता को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि पासपोर्ट अपने-आप में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नागरिकता का निर्धारण केवल किसी एक दस्तावेज से नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के आधार पर होता है। यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिकों के भरोसे से भी जुड़ा है। आम नागरिक का सबसे बड़ा सवाल यही है-यदि आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर भारतीय नागरिकता सिद्ध कैसे होगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति नागरिक का विश्वास होता है। यदि नागरिक को अपने ही अधिकारों के प्रमाण को लेकर असमंजस रहे, तो यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इसलिए समय की मांग है कि नागरिकता प्रमाणन की प्रक्रिया स्पष्ट, सर्वसुलभ और विवाद-मुक्त बनाई जाए, ताकि किसी भी भारतीय को अपनी नागरिकता साबित करने के प्रश्न पर अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पहचान और नागरिकता एक जैसी नहीं हैं। आधार कार्ड आपकी पहचान और निवास का प्रमाण है। वोटर आईडी मतदान के अधिकार का प्रमाण है। पैन कार्ड आयकर संबंधी पहचान है। ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा और अंतरराष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज है। लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज अकेले नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता।

आखिर नागरिकता कैसे तय होती है? भारत में नागरिकता का आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 है। इस कानून के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार हैं-जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण द्वारा, किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है तो संबंधित प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों, जन्म संबंधी अभिलेखों, माता-पिता की नागरिकता, सरकारी रिकॉर्ड तथा अन्य कानूनी साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करता है। कोई एक दस्तावेज हर परिस्थिति में निर्णायक नहीं होता।

हाल के वर्षों में जन्म प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण आधार दस्तावेजों में माना जाने लगा है, क्योंकि इससे जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। लेकिन जिन लोगों का जन्म दशकों पहले हुआ और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए स्कूल प्रमाणपत्र, भूमि अभिलेख, पारिवारिक रिकॉर्ड, सरकारी सेवा अभिलेख तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक किस दस्तावेज पर भरोसा करे। दूसरी ओर सत्तापक्ष का तर्क है कि दुनिया के अनेक देशों में भी पासपोर्ट नागरिकता निर्धारण का एकमात्र कानूनी आधार नहीं होता और विवाद की स्थिति में मूल नागरिकता रिकॉर्ड ही निर्णायक होते हैं। यह बहस संसद से लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों तक फैल चुकी है।

इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में आज तक ऐसा कोई एकल राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है जिसे हर स्थिति में अंतिम माना जाए। परिणामस्वरूप लोग आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को ही नागरिकता का प्रमाण समझ लेते हैं, जबकि कानून की दृष्टि से इनकी भूमिका अलग-अलग है।

लोकतंत्र में केवल कानून होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका स्पष्ट और सरल संप्रेषण भी आवश्यक है। यदि नागरिकों में यह भ्रम बना रहे कि कौन-सा दस्तावेज वैध है और कौन-सा नहीं, तो इससे अनावश्यक भय और अफवाहें फैल सकती हैं।

सरकार को चाहिए कि नागरिकता प्रमाणन संबंधी एक स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे, जिसमें बताया जाए कि विभिन्न परिस्थितियों में कौन-कौन से दस्तावेज स्वीकार्य होंगे। इससे प्रशासनिक विवाद भी कम होंगे और नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

हर नागरिक को अपने जन्म, शिक्षा, परिवार और संपत्ति से जुड़े मूल सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और समय-समय पर उनका अद्यतन कराना भी आवश्यक है। भविष्य में किसी भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान यही रिकॉर्ड सबसे अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। नागरिकता केवल एक कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। इसलिए इस विषय पर राजनीति से अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता की आवश्यकता है। नागरिकों को भ्रमित करने के बजाय सरकार को एक सरल, एकीकृत और पारदर्शी नागरिकता प्रमाणन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

अब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज वैध है जिसे नागरिक प्रस्तुत कर अपनी नागरिकता सिद्ध कर सके। इस सबका एक ही निराकरण है कि केंद्र सरकार को सर्वप्रथम एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस नागरिकता पर स्पष्टता करनी चाहिए। ताकि देश में इसको लेकर किसी के मन में भ्रम न हो।

(लेखक- सौरभ वार्ष्णेय)
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

मुख्यमंत्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित वेदी प्रतिष्ठा समारोह हुईं शामिल

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पीतमपुरा स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित वेदी प्रतिष्ठा समारोह एवं जिन बिम्ब स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्तीसागर महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जैन दर्शन का अहिंसा, सत्य, तप और संयम का संदेश मानवता को आत्मानुशासन, करुणा और सदाचार का मार्ग दिखाता है। यही शाश्वत मूल्य एक संवेदनशील, समरस और सशक्त समाज की आधारशिला हैं।

द्वारका में नवंबर तक बन जाएगा पहला डॉग शेल्टर

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए एमसीडी प्रशासन कई डॉग शेल्टर बनवा रहा है। द्वारका सेक्टर-29 में बनवाया जा रहा निगम का पहला डॉग शेल्टर नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें लगभग 1500 लावारिस कुत्तों के रखने की क्षमता होगी। ढाई एकड़ के इस शेल्टर होम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा लावारिस कुत्तों की गिनती करने के लिए भी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निदेशों का पालन करते हुए लावारिस कुत्तों की समस्याओं को दूर करने पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर तीन स्थानों पर डॉग शेल्टर बनाने का काम शुरू किया गया है। पहला डॉग शेल्टर इस वर्ष नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बिजवासन बेला रोड व अन्य स्थानों पर बन रहे डॉग शेल्टर होम को जल्द तैयार किया जाएगा। अब तक आठ सौ से अधिक डॉग फीडिंग बिंदुओं को भी तैयार कर लिया गया है।

लड़कियों का पीछा कर वीडियो बनाने वाला सामाजिक माध्यम संचालक गिरफ्तार

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली पुलिस की साइबर इकाई ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को कथित रूप से सड़क पर परेशान करने तथा उनके वीडियो बिना अनुमति सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान गुरमान सिंह के रूप में हुई है, जो 'रोड सेफ्टी वाला' नाम से सामाजिक माध्यम मंच संचालित करता था। पुलिस के अनुसार, गुरमान सिंह पर आरोप है कि वह सड़क पर चल रही महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की दोपहिया वाहनों को जानबूझकर टक्कर मारता था, उनका पीछा करता था और उन पर अभद्र टिप्पणियां करता था। इसके बाद वह उनके वीडियो बनाकर विभिन्न सामाजिक माध्यम मंचों पर साझा करता था।

गोल्डी ढिल्लों गिरोह के दो सहयोगी गिरफ्तार

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात अपराधी गोल्डी ढिल्लों गिरोह के दो प्रमुख सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रोहिणी क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपितों के कब्जे से एक अर्द्ध स्वचालित पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल तथा कई जीवित कारतूस बरामद किए हैं।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जतिन भारद्वाज उर्फ नन्नू और सुखविंदर सिंह उर्फ बग्गा के रूप में हुई है। दोनों पंजाब के राजपुरा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित गिरोह के लिए हथियारों और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अपराध शाखा की लूट निरोधक एवं विशेष प्रकोष्ठ इकाई पिछले कई महीनों से विदेश में बैठे अपराधियों द्वारा व्यापारियों को दी जा रही रंगदारी की धमकियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गोल्डी ढिल्लों गिरोह से जुड़ा जतिन भारद्वाज किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से रोहिणी क्षेत्र में आने वाला है।

बदलते मौसम का असर

त्वचा रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी

राजधानी में मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर अब लोगों की त्वचा पर भी दिखाई देने लगा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप के कारण त्वचा संबंधी रोगों के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। सरकारी और निजी चिकित्सालयों के त्वचा रोग विभागों में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

नई दिल्ली,वेब वार्ता

चिकित्सकों के अनुसार, वातावरण में बढ़ी नमी, अत्यधिक पसीना और अचानक बदलते तापमान के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। लाल चकत्ते, खुजली, जलन, फफूंद जनित संक्रमण और घमौरियों जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से शरीर के वे हिस्से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जहां लगातार नमी बनी रहती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में अचानक परिवर्तन होने पर शरीर को स्वयं को अनुकूल बनाने में समय लगता है। इस दौरान त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे संक्रमण और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के बाद बढ़ी आर्द्रता तथा उसके तुरंत बाद निकलने वाली तेज धूप त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। पसीने, गंदगी और जीवाणुओं के तेजी से पनपने से संक्रमण की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान त्वचा एलर्जी और फफूंद जनित संक्रमण के मामलों में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से एलर्जी से पीड़ित लोगों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है।

डॉ. मनीष जागड़ा ने बताया कि इस मौसम में लोगों को दिन में कम से कम दो बार स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद शरीर के मुड़ने वाले हिस्सों को अच्छी तरह सुखाना चाहिए, ताकि वहां नमी न बनी रहे। उन्होंने पुराने अंतर्वस्त्रों को बदलने तथा केवल सूती अंतर्वस्त्र पहनने की सलाह दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि त्वचा को साफ और सूखा रखने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना आवश्यक है। यदि त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, जलन या संक्रमण के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। साथ ही, गीले कपड़े लंबे समय तक नहीं पहनने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। चिकित्सकों का मानना है कि समय पर उपचार और सावधानी बरतकर गंभीर संक्रमण की संभावना को काफी हद तक रोका जा सकता है।

आरके पुरम में जन चौपाल, सुरक्षा और अवैध पार्किंग की समस्याएं रखीं

वेब वार्ता, नई दिल्ली

दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में लोगों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा विधायक अनिल शर्मा और दक्षिण पश्चिम जिले के जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने लोगों की समस्याएं सुनीं।

जन चौपाल में लोगों ने अवैध पार्किंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की गतिविधियों, ट्रैफिक व्यवस्था, संदिग्ध लोगों की आवाजाही और कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने सभी शिकायतों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा, पुलिस और जनता के बीच संवाद से ही सुरक्षित समाज का निर्माण हो सकता है।

संस्कृत भाषा और गीता के ज्ञान से नई पीढ़ी को मिलती है राष्ट्र निर्माण की प्रेरणाः सत्या शर्मा

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शनिवार को वसंत कुंज स्थित संस्कृत भारती गुरुकुल में आयोजित 'गीता शिक्षण केन्द्रस्य अभ्यासवर्ग' कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और आचार्यों से संवाद करते हुए भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा तथा श्रीमद्भगवद्गीता के अमूल्य ज्ञान पर विस्तार से चर्चा की।

सत्या शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश आज भी समाज और मानव जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों वर्ष पहले था। उन्होंने कहा कि गीता जीवन में कर्तव्य, नैतिकता और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम केवल धार्मिक या शैक्षणिक आयोजन नहीं होते, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है और उनमें राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होती है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने संस्कृत भारती गुरुकुल के आचार्यों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत और गीता के अध्ययन को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

क्लीन यमुना मिशन को जन आंदोलन बनाएं : रविकांत

नई दिल्ली, वेब वार्ता

त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविकांत ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की आस्था, संस्कृति और जीवनरेखा है। इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है।

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित क्लीन यमुना मिशन के अंतर्गत आयोजित होने वाले यमुना सफाई अभियान की तैयारियों के मद्देनजर विधायक रविकांत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चिल्ला यमुना घाट का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था, सफाई कार्यों की प्रगति तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार पूर्व जिला के महामंत्री सुनील गुप्ता तथा जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र डेढ़ा भी उपस्थित रहे।

विधायक रविकांत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे यमुना को स्वच्छ बनाने के प्रयासों को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे स्वच्छ यमुनाझ्रविकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए क्लीन यमुना मिशन को जन-जन का अभियान बनाएं और यमुना की स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

नगर निगम एक वर्ष में तीन बहुमंजिला पार्किंग बनाएगा

नई दिल्ली,वेब वार्ता। राजधानी में तीन स्थानों पर बहुमंजिला कार पार्किंग की सुविधा विकसित होगी। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। योजना के मुताबिक, एक साल में जंगपुरा, कालकाजी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण होगा। इसमें 400 से अधिक कारें पार्किंग की सुविधा मिलेगी।

नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, तीनों स्थानों पर बहुमंजिला कार पार्किंग बनाने में 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके अलावा दिल्ली में कई अन्य स्थानों पर सरफेस पार्किंग बनाने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। 20 से अधिक स्थानों पर अगले दो महीने में सरफेस पार्किंग को तैयार किया जाएगा। इसमें पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, रोहिणी समेत कई प्रमुख बाजार शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अवैध पार्किंग को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पार्किंग शुल्क को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए सभी पार्किंग में हाथों से संचालित होने वाले डिवाइस को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा निगम के सभी 450 से अधिक पार्किंग स्थलों पर उन मशीनों को भी कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा है, जिसके जरिये पार्किंग शुल्क की रसीद वाहन चालकों को उपलब्ध कराई जाती है। निगम के अधीन सभी जोन में लगभग 30 बहुमंजिला और 420 से अधिक सरफेस पार्किंग संचालित होती है।

अवैध वसूली की ऐप पर करें शिकायत

निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम की कई पार्किंग में शुल्क से अधिक वसूलने की शिकायतें आ रही हैं। वाहन चालक इसकी शिकायत निगम के ऐप 311 और हेल्पलाइन नंबर 155305 पर कर सकते हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सभी पार्किंग में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों को अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वह पार्किंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत नगर निगम प्रशासन से कर सकते हैं।

डीडीए को सरफेस पार्किंग बनाने का जिम्मा

डीडीए भी दिल्ली के कई स्थानों पर सरफेस पार्किंग का निर्माण करेगा। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि द्वारका, उत्तरी दिल्ली, रोहिणी, पूर्वी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली में 200 से अधिक सरफेस पार्किंग तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त कड़कड़डूमा, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिलशाद गार्डन, द्वारका व अन्य स्थानों पर बहुमंजिला कार पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी।

दिल्ली भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों का पुनर्गठन किया

उत्तर बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ जिले का पुनर्गठन अभी होना बाकी

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को नई धार देते हुए शुक्रवार को 14 में से 11 जिलों का पुनर्गठन कर दिया गया। प्रत्येक जिले में स्थानीय समीकरणों को साधते हुए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गइ है। एक तिहाई पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि युवाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने सामाजिक समावेश का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अगुवाई में पुनर्गठन ऐसे समय में किया गया है जब पार्टी दिल्ली में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पुनर्गठन में कुछ नए मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा इस सूची के साथ की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के कुल 14 संगठनात्मक जिले हैं, इनमें से 11 जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। इनमें मयूर विहार, उत्तर पूर्वी, करोल बाग, शाहदरा, नई दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी दिल्ली, केशवपुरम, महरौली और नवीन शाहदरा शामिल हैं। प्रत्येक जिले में छह उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, छह मंत्री समेत 22 पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। शेष तीन जिले उत्तर बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची उनके जिलाध्यक्षों से परामर्श के बाद जल्द जारी करने की बात कही गई है। राजनीतिक दृष्टि से यह पुनर्गठन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से भाजपा लगातार संगठन को पहले से अधिक सुदृढ़ करने में जुटी है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यह नई संगठनात्मक व्यवस्था दिल्ली की जनता की सेवा के लिए पार्टी को और अधिक ऊजार्वान बनाएगी।

जन्मदिन से पहले सड़क हादसे में युवक की मौत

नई दिल्ली,वेब वार्ता

वसंतकुंज दक्षिण क्षेत्र के रजोकरी फ्लाईओवर पर हुई सड़क दुर्घटना में गुरुग्राम निवासी 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार, 25 जून को रजोकरी फ्लाईओवर पर एक थार वाहन ने सार्थक मट्टू की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सार्थक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका जन्मदिन दो दिन बाद आने वाला था।

भीषण गर्मी में सेवा कामना ट्रस्ट की निःशुल्क शरबत सेवा जारी

नई दिल्ली, वेब वार्ता। भीषण गर्मी के बीच सेवा कामना वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा राजधानी में पिछले एक माह से लगातार निःशुल्क मीठे शरबत का वितरण किया जा रहा है। इस सेवा का उद्देश्य राहगीरों, मजदूरों और सड़क से गुजरने वाले लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करना है।

ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती अनु भाटिया ने बताया कि कई बार शरबत तैयार किए जाने के दौरान ही प्यासे लोग पहुंच जाते हैं और ठंडा होने का इंतजार किए बिना ही शरबत लेने का आग्रह करते हैं। ऐसे क्षण यह एहसास कराते हैं कि किसी की प्यास बुझाना मानवता की सच्ची सेवा है।

उन्होंने कहा कि थके हुए चेहरों पर मुस्कान लौटते देखना और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना ही इस सेवा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसी प्यासे व्यक्ति को संतुष्टि के साथ शरबत पीते देख ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने इस छोटी-सी सेवा को स्वीकार कर लिया हो। इस अभियान में क्षेत्रवासियों का निरंतर सहयोग मिल रहा है। उनके सहयोग और विश्वास के बल पर सेवा कामना टीम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रही है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद में पाँच वर्षों से रुके कार्यों को आगे बढ़ाने में सफलता

डॉ. शम्स इकबाल के प्रयास सराहनीय : डॉ. सैयद अहमद खाँ

वेब वार्ता, नई दिल्ली

उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सैयद अहमद खाँ ने कहा कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) में पिछले पाँच वर्षों से रुके हुए कार्यों को दोबारा गति देने में डॉ. शम्स इकबाल की मेहनत और सक्रिय भूमिका सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उर्दू भाषा के संवैधानिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। संगठन के संस्थापक महासचिव डॉ. परवाजुल उलूम तथा डॉ. लाल बहादुर के प्रयासों से उर्दू के पक्ष में कई महत्वपूर्ण मुकदमों में सफलता मिली है।

डॉ. सैयद अहमद खाँ ने कहा कि 4 सितंबर 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी साहित्य

सम्मेलन के विरुद्ध मामले में मिली जीत उर्दू के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यदि उस मामले में हिंदी साहित्य सम्मेलन सफल हो जाता, तो सात राज्यों में उर्दू को प्राप्त द्वितीय राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्रभावित हो सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की बहुभाषी परंपरा को स्वीकार करते हुए उर्दू के अधिकारों की रक्षा की।

उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों की उर्दू अकादमियों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संबंधित अधिकारियों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र भेजे हैं, जिन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि उर्दू समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए प्रयास करेगा तो भविष्य में भी महत्वपूर्ण सफलताएँ मिलेंगी।

लाल किला धमाका : तीन और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

वेब वार्ता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले साल दिल्ली लाल किला बम धमाके में तीन और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें एक फरार पीडियाट्रिशियन (बच्चों का डॉक्टर) भी शामिल है, जिसकी पहचान एक आतंकी मॉड्यूल के संस्थापक सदस्य के रूप में हुई।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल पूरक आरोप पत्र में जमीर

मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था मुजफ्फर

एनआईए की जांच में पता चला कि मुजफ्फर उन मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था जिनके साथ सह-आरोपी उमर, मुजम्मिल, अदील और मुफ्ती इरफान भी शामिल थे। इनकी साजिश के कारण 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास धमाका हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। बयान में कहा गया कि एनआईए की जांच से पता चला कि मुजफ्फर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर और मुजम्मिल द्वारा चलाई जा रही एक गुप्त जगह पर टीएटीपी-बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने, उनकी टेस्टिंग और उन्हें सुरक्षित रखने के काम में गहराई से शामिल था। टीएटीपी या ट्राईएसीटोन ट्राईपरॉक्साइड घर पर बनाया जाने वाला एक विस्फोटक है। जांच एजेंसी ने बताया कि मुजफ्फर के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट और फरार मुजफ्फर अहमद (उर्फ फराज उर्फ जफर) को आरोपी बनाया है। ये सभी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी भी शामिल है, जो विस्फोटक से भरी कार का ड्राइवर थ और धमाके में मारा गया था। एनआईए के बयान के मुताबिक, पीडियाट्रिशियन (एमबीबीएस, एमडी) मुजफ्फर अहमद सह-आरोपी डॉ. अदील अहमद राथर का बड़ा ााई और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) का संस्थापक सदस्य है। यह संगठन अल-कायदा से जुड़ा है।

एजीयूएच का गुप्त सहायक था जमीर

एनआईए की जांच के मुताबिक, जमीर एजीयूएच का एक गुप्त सहायक (ओजीडब्ल्यू) था, हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था और टेरर मॉड्यूल के लिए हथियार, गोला-बारूद और कैश पहुंचाने का काम करता था। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का पूर्व ओजीडब्ल्यू तुफैल, इस मॉड्यूल के लिए हथियार सप्लाई करता था। एजेंसी ने बताया कि तुफैल ने एक हैंडलर के जरिए ह्यडेड ड्रॉपह्न (गुप्त रूप से सामान छोड़ने की जगह) से एक एके-47, एक क्रिंकोव राइफल, एक पिस्टॉल, मैगजीन और जिंदा कारतूस मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (जो अब मर चुका है) को 3 लाख रुपये में पहुंचाए थे।

संक्षिप्त वार्ता

आम बेच रहे फल विक्रेता को रौंदते हुये जिला पंचायत सदस्य के घर में घुसी बेकाबू स्कॉर्पियो

वेब वार्ता, हरदोई

कछौना थाना क्षेत्र के समोधा-दलेलनगर बाजार में शुक्रवार (26 जून) शाम करीब सात बजे तेज एवं लापरवाही से चलाई जा रही स्कॉर्पियो (UP 32 JX 5152) ने सड़क किनारे आम बेच रहे फल विक्रेता अरुण पुत्र रामखेलावन, निवासी दलेलनगर समोधा, को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अरुण की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बेकाबू स्कॉर्पियो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य शांति वर्मा के मकान में जा घुसी। इस दौरान उनके पति डॉ. सुमेर कुमार वर्मा घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है। वाहन चालक आशीष दिवाकर पुत्र छत्रपाल, निवासी तियाराहार दलेलनगर समोधा, थाना कछौना, को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना कछौना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) सुबोध गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना चालक की तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई। मामले की विवेचना जारी है।

पंजीकरण विभाग के मॉड्यूल लागू करने पर रोक की मांग

वेब वार्ता, जलालाबाद (शाहजहांपुर)

बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ एवं स्टाम्प विक्रेता संघ ने पंजीकरण विभाग के प्रस्तावित मॉड्यूल के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अधिवक्ता संगठनों का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और अन्य हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श कर जनहित में व्यवहारिक समाधान निकाला जाए। उनका कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था नागरिकों के संपत्ति अधिकारों और न्याय तक पहुंच से जुड़ी है, इसलिए बिना पर्याप्त तैयारी इसे लागू करना उचित नहीं होगा। चेतावनी दी गई कि मांगें नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन, धरना-प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार और अन्य लोकतांत्रिक विरोध कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और निबंधन विभाग की होगी। अधिवक्ताओं की यह हड़ताल शनिवार को 16 वे दिन भी जारी रही।

गांव मझारा में विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

वेब वार्ता, शाहजहांपुर

जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मझारा में 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार मृतका मीनू पत्नी सुरजीत, पुत्री अनिल कुमार यादव की शादी करीब तीन वर्ष पहले हुई थी। ससुराल पक्ष और ग्रामीणों ने बताया कि विवाहिता ने फांसी लगाई थी, जबकि उसके पिता ने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की। सूचना पर एफएसएल टीम को बुलाया गया और एसडीएम को अवगत कराया गया। नायब तहसीलदार अनुराग दुबे की मौजूदगी में महिला उपनिरीक्षक काजल ने पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शनिवार दिन के 12:00 बजे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हेरिटेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट से बदल रही काशी की काल भैरव गली

वेब वार्ता, वाराणसी

उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी जनपद में नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद्रा ने शनिवार को कहा कि हेरिटेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत काशी में काल भैरव मंदिर जाने वाली मार्ग (गली) का सौंदर्यीकरण एवं पुनर्स्थापन कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर की मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्य अभियंता ने कहा कि यह प्रयास हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना पडा भारी

सप्ताह भर में हुए 1400 चालान

वेब वार्ता, कानपुर

शासन के दिशा-निदेर्शों के अनुपालन में पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में कानपुर आरटीओ अव्वल रहा। आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस और प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कड़े एक्शन के तहत अकेले एक सप्ताह के भीतर कुल 1400 वाहनों के चालान किए गए, जबकि हालिया कार्रवाई में विभिन्न आरोपों में 307 वाहनों पर गाज गिरी।

कानपुर मण्डल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमो की अनदेखी करने वालो पर विभाग सख्ती से कार्यवाही करने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत पूरे प्रदेश भर में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप, एचएसआरपी नम्बर प्लेट पर अभियायन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर नगर के सचेंडी, घाटमपुर, नौबस्ता ,सचेती और चौबेपुर क्षेत्रो में एआरटीओ तृतीय दल सोमलता यादव व पीटीओ दीपक सिंह ने ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त चेकिंग चलाया और पूरे सप्ताह में 1400 वाहनो के विभिन्न अभियोग में चालान की कार्यवाही की गई। आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

इन अभियोगो पर हुई प्रवर्तन की कार्यवाही

आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान में मुख्यतः बिना एचएसआरपी के 48 वाहनों, रेट्रो टेप के तहत 59, बिना हेलमेट के अभियोग में 104, बिना सीट अभियोग में 31, ओवरलोड में 8, रॉन्ग साइड पर 84 व वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग करने पर 21 चालान किये गये।

फायर अधिकारियों ने हॉस्पिटल के स्टाफ ,सुरक्षागार्ड व नर्सिंग स्टाफ को दिया प्रशिक्षण

कानपुर। लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर जिला प्रशासन ने अग्नि शमन यंत्रों और सुरक्षा की दृष्टि से सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में फायर सिस्टम की अनिवार्यता को लागू कर दिया है। जिसके क्रम में एलएलआर हॉस्पिटल के मैटरनिटी विंग के पास फजलगंज फायर स्टेशन अधिकारियों द्वारा हॉस्पिटल के स्टाफ कर्मचारियों ,सुरक्षागार्ड नर्सिंग स्टाफ को फायर से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया और आपातकाल में उनसे निपटने के गुर बताए। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सौरव अग्रवाल ने बताया की अस्पताल परिसर में अग्नि से सुरक्षा के लिए सभी उपकरण एवं फायर सिस्टम तथा फायर अलार्म पूरी तरह से काम कर रहे हैं।

आज फायर अधिकारियों द्वारा अग्नि से बचाव और किस लोगो को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है उसे बारे में उन्हें प्रशिक्षित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी।

ज्येष्ठ के अंतिम शनिवार पर युवा उद्यमी सूर्या गुप्ता ने कराया विशाल भंडारा, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

हरदोई। ज्येष्ठ माह के अंतिम शनिवार को कस्बा कछौना में युवा उद्यमी सूर्या गुप्ता उर्फ लिटिल द्वारा अपने निज निवास, बनियनखेड़ा में विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया। भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस सेवा कार्य में राहगीरों, महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

भंडारे में श्रद्धालुओं को बूंदी, पूड़ी एवं सब्जी का प्रसाद वितरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक आस्था, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव का वातावरण बना रहा।

ज्येष्ठ माह में भगवान हनुमान की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में सेवा, दान, जलपान, शर्बत वितरण एवं भंडारे जैसे धार्मिक आयोजनों से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा समाज में परोपकार और भाईचारे की भावना मजबूत होती है।

भंडारे में क्षेत्र के प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि, सभासद, शिक्षक एवं व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। प्रमुख रूप से व्यापार मंडल संरक्षक रामखेलावन गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरव गुप्ता, मनोज गुप्ता, निलेश गुप्ता, रुद्र प्रताप सिंह, युवा नेता संचित अग्रवाल, गौतम कनौजिया, श्रीश मिश्रा, रविंद्र कुमार सिंह, दुर्गेश सिंह, लालन गुप्ता, पूर्व सभासद धर्मेंद्र सिंह, मुकेश कुमार सिंह उर्फ गोलू, बबलू गुप्ता, अंशु गुप्ता, रामू गुप्ता, सी.एस. गुप्ता, रोहित गुप्ता, युवा कवि अवलोक श्रीवास्तव, शिक्षक अमृतलाल शर्मा, आशुतोष प्रजापति, मैनेजर बसंत सिंह, मनीष सिंह, आलोक राठौर, योगेंद्र राठौर, धीरेंद्र गुप्ता, भल्ले अग्रवाल, पंकज यादव, लालता सिंह, मनीष चौरसिया, विनय तिवारी एवं अनिल गुप्ता उर्फ मंटू सहित अनेक लोगों ने सहयोग किया।

आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में प्रेम, सहयोग, सद्भाव और सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति एवं सेवा का वातावरण बना रहा।

देवरिया में पेड़ के नीचे आराम कर रहे डिलीवरी मैन को चार पहिया वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

वेब वार्ता, देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देवरिया नगर के चीनी मिल मैदान में पेड़ के नीचे तेज धूप में शनिवार की दोपहर में आराम कर रहे रसोई गैस के डिलीवरी मैन को चार पहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर पेड़ में वाहन से दबा दिया। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई।आस पास के लिए उन्हें उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की इमरजेंसी ले आए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद वाहन छोड़ कर चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार देवरिया नगर में मृतक लक्ष्मण साहनी उम्र 40 वर्ष पुत्र विश्वनाथ निवासी भटवलिया नाथ नगर के रहने वाले थे। वह रसोई गैस डिलिवरी करते थे। रसोई गैस पहुंचाने के बाद धूप लगने पर वह दोपहर में चीनी मिल मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठ गए । इस बीच एक युवक तेज गति से जिप्सी चलाते हुए आया और अनियंत्रित होकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। आस पास खड़े कुछ लोग भाग कर अपनी जान बचा लिए लेकिन लक्ष्मण साहनी नहीं भाग पाए और वाहन की चपेट में आ गए।जिप्सी व पेड़ के बीच वह दब गए। जिससे उनके सीने की हड्डियां टूट गई। उन्हें मेडिकल कालेज पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में देवरिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना हुई है। शव को विधिक के लिए भेजा गया है।

मोहर्रम जुलूस के दौरान छज्जा गिरा, दो बच्चों की मौत

वेब वार्ता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात मोहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान एक छज्जा पर लोग खड़े थे। ज्यादा भार होने से छज्जा भरभरा कर गिर गया। इस घटना में दो बच्चोंक मौत हो गई। आठ लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया है। एसीपी बीकेटी विकास कुमार पांडेय ने बताया कि थाना इटौंजा क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला पखरिया, मोहना में एक मकान के छज्जे से लोगों को पेय पदार्थ वितरित किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक छज्जा भरभराकर गिर गया। उसकी चपेट में आकर 10 लोग घायल हो गए। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय बीकेटी भेजा गया।

दो बूंद जिंदगी की के लिए हरदोई तैयार

पल्स पोलियो महाअभियान कल से, निकली विशाल जागरूकता रैली

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जनपद में 28 जून से 6 जुलाई 2026 तक चलने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवनाथ पांडेय ने गांधी भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने गगनभेदी नारों के माध्यम से लोगों को अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने के लिए जागरूक किया।

रैली में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता, आशा संगिनी, एएनएम तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। रैली का संचालन जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने किया। इस दौरान अर्बन नोडल एनयूएचएम, सीएमओ कार्यालय के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर तथा गावी-जेएसआई के जिला समन्वयक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि अभियान के पहले दिन 28 जून को 'बूथ दिवस' मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में 1,792 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके बाद 29 जून से 6 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी, जो पहले दिन किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जनपद के 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 5 लाख 32 हजार बच्चों को 'दो बूंद जिंदगी की' पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ईंट-भट्टों, निर्माण स्थलों और अन्य हाई-रिस्क क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो रोधी दवा से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए उन्हें नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं।

विवाहित युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ घर में फाँसी लगाकर की आत्महत्या

वेब वार्ता, हरदोई। कोतवाली कछौना के अंतर्गत ग्राम चौरा में विवाहित युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ शुक्रवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव समेत पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह परिजनों को जानकारी हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गये। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली कछौना टीम, क्षेत्राधिकारी प्रभा पटेल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने पहुंचकर दोनों समन को उतरवा कर विधि कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया।

कोतवाली कछौना के ग्राम चौरा मजरा पतसेनी देहात में जवाहर का 30 वर्षीय पुत्र श्रवण ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। जवाहर की पुत्री थाना बेनीगंज ग्राम फत्तेपुर में ब्याही थी। जहां पर जवाहर के पुत्र श्रवण का लगभग 2 वर्ष से अधिक समय से आना जाना था। इसी बीच फत्तेपुर में सोबरन की पुत्री कुंती से उसका प्रेम प्रसंग हो गया जिसको लेकर परिवार में वाद विवाद होता था। इन दोनों के संबंधों को लेकर बीती 23 जून को ग्राम फत्तेपुर में विवाद हुआ था। परिजनों की शिकायत पर श्रवण का शांति भंग में चालान भी हुआ था। 24 जून को श्रवण अपने गांव चौरा वापस आ गया था। 25 जून को कोतवाली कछौना के पास स्थित लंगड़े दास बाबा कुटी मंदिर के परिसर में श्रवण व प्रेमिका के मध्य स्थानीय लोगों की मौजूदगी में सुलह समझौता हुआ। लड़की के भाई ने कहा कि तुम श्रवण के साथ जाकर रहो और हमारे परिवार व दुनिया से दूर हो जाओ। श्रवण अपनी प्रेमिका कुंती को लेकर अपने गांव चौरा आ गया। मृतक श्रवण के तीन मासूम बच्चे हैं। 26 जून को दोनों ने संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फांसी लगा ली जिसकी जानकारी परिजनों को तड़के सुबह हुई। थोड़ी देर में यह घटना पूरे क्षेत्र आग की तरह में फैल गई। आला अधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी बिंदुओं की गहन जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाये। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि घटना से सम्बंधित सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी प्रभा पटेल के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई। मृतक के बुजुर्ग माता-पिता नेत्रहीन हैं, साथ ही पत्नी व बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है।

हनुमानगढ़ी उज्जैनिया पट्टी के श्रीमहंत संतराम दास का निधन

वेब वार्ता, अयोध्या

हनुमानगढ़ी उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत संतराम दास महाराज शनिवार को गोलोकवास (निधन) हो गए थे। उनके शिष्य महंत राजू दास ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आज शनिवार को अपराह्न शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार आज शाम नया घाट सरयू तट (कच्चा घाट) पर किया जाएगा।

कोई बच्चा पोलियो की खुराक से न रहे वंचितः शशांक मणि

देवरिया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत शनिवार को जिले में पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सदर सांसद शशांक मणि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिलाधिकारी आवास, सिविल लाइन रोड, बस स्टैंड होते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मुख्य रैली के माध्यम से लोगों को पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए जागरूक किया गया। रविवार को जिलेभर में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ होगा।

पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज से निकाली गई जन जागरूकता रैली

सदर सांसद शशांक मणि ने कहा कि अभियान के तहत पांच वर्ष तक के 5.68 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को दो बूंद जिंदगी की पिलाने की अपील की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान की निगरानी के लिए 286 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीएचओ समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसके सिन्हा ने कहा कि रविवार को पहले दिन जिले में 1759 फिक्स्ड बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

कुशीनगर में बाढ़, बचाव का काम अधूरा, बारिश के बाद रेनकट ने बढ़ाई मुश्किलें

बैराज से छूटा पानी तो मचेगी तबाही

वेब वार्ता, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में समय बीतने के बाद भी बाढ़ से बचाव का कार्य पूरा नहीं हो सका है। विगत बृहस्पतिवार की रात हुई बारिश से एपी, नरवाजोत और छितौनी तटबंध पर 300 से अधिक रेनकट ने तटवर्ती लोगों की और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। छितौनी बंधे पर पांच ठोकर बने हैं, जहां अधिक रेनकट है। नदी के जलस्तर पर में वृद्धि होने लगी है। नारायणी नदी(बड़ी गंडक) चेतावनी बिंदु से 68 सेमी नीचे बह रही है। लोगों का कहना है कि अचानक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो तबाही मचनी तय है। बारिश के बाद बंधे पर बने रेनकट को ठीक कराने के लिए एक्सईएन ने बाढ़ खंड को निर्देश दिए हैं।

एपी बांध व नरवाजोत बांध पर स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य जून के अंतिम सप्ताह में भी पूरा नहीं होने से बंधे के किनारे बसे गांवों के लगभग बीस हजार से अधिक आबादी को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। लोगों का कहना है कि बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो बचाव कार्य प्रभावित होने के साथ तटबंधों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है।

वर्तमान में एपी बांध व नरवाजोत बांध पर सुरक्षात्मक कार्य को लेकर 32.71 करोड़ की लागत की तीन परियोजनाएं चल रही हैं। बाढ़ खंड की ओर से मार्च से ही बांध पर सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। नरवाजोत बांध पर दो व एपी बांध पर एक परियोजना चल रही है। पहली परियोजना के तहत 11.32 करोड़ की लागत से नरवाजोत बांध पर किमी 1.700 पर स्थित स्पर के नोज भाग के साथ ट्रांजिट एप्रन एवं किमी 1.950 से किमी 2.100 के बीच रिवेटमेंट पुनर्स्थापना का कार्य तथा किमी 0.000 से किमी 0.100 के बीच रिवेटमेंट और तीन पंक्ति में परक्यूपाइन का निर्माण चल रहा है, लेकिन यहां ठोकर के साथ अप एंड डाउन स्ट्रीम का कार्य अधूरा है, जबकि यह सर्वाधिक संवेदनशील हिस्सा है।

दूसरी परियोजना में 11.66 करोड़की लागत से नरवाजोत बांध पर स्थित किमी 0.525 से किमी 0.825 के बीच और किमी 0.825 से किमी 1.000 के बीच रिवेटमेंट पुनर्स्थापना कार्य के साथ किमी 0.525 से किमी 1.000 के बीच तीन पंक्ति में परक्यूपाइन का निर्माण हो रहा है। यहां रिवेटमेंट का कार्य अब भी अधूरा है।

तीसरी परियोजना के तहत 9.72 करोड़ की लागत से एपी बांध के जवही दयाल में किमी 3.500 से किमी 4.000 के बीच रिवेटमेंट कार्य एवं तीन पंक्ति में परक्यूपाइन का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य की रफ्तार धीमी है। कहीं स्लोप तो कहीं पैच और कई जगहों पर तो रिवेटमेंट का कार्य भी अधूरा है। हालांकि तीनों साइट पर जेई रमेशधर दुबे, सुनील कुमार यादव, विनोद शर्मा आदि कार्य पूरा कराने में लगे हैं। बाढ़ बचाव कार्य पूरा न होने से ग्रामीणों को बाढ़ व कटान का भय सताने लगा है। छितौनी बंधे पर पांच ठोकर हैं, जहां रेनकट अधिक है। भैंसहा गेज की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार की शाम चार बजे 94.32 मीटर पर नदी प्रवाहित हो रही थी।

खान सर केस में फिर बढ़ी तारीख, बॉडीगार्ड को फिलहाल जेल में बिताने होंगे दिन

पटनाः फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

कोर्ट ने अपडेटेड केस डायरी पढ़ने के लिए दोनों पक्षों को तीन दिन का समय दिया. इस दौरान खान सर को 30 जून तक अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. आज कदमकुआं थाने ने अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश की गई. साथ ही बॉडीगार्ड्स की जमानत पर भी सुनवाई मंगलवार को ही होगी. खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आज ही सुनवाई पूरी कर दी जाए. लेकिन रौशन आनंद के पक्ष की ओर से वकील सत्यम झा ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि डायरी अभी-अभी आई है, इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए. कोर्ट ने सत्यम झा की मांग स्वीकार करते हुए तीन दिन का समय दिया. मामले को 30 जून

के लिए स्थगित कर दिया.

रौशन आनंद विवाद से शुरू हुई पूरी कहानी

खान सर पर रौशन आनंद सर ने लगाए आरोप

जमानत के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उनके भाई की मौत और जेल में जानलेवा हमले की साजिश का जिक्र किया गया. खान सर के सुरक्षा गार्डों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. वे अभी भी जेल में हैं. आज की सुनवाई में डायरी पढ़ने के लिए समय मिलने से उनके रिहाई की प्रक्रिया और लंबी हो गई है.

यह मामला दो कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है. 2 जून 2026 को पटना के कदमकुआं इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज (खान सर की कोचिंग) पर कथित तौर पर हमला हुआ. पत्थरबाजी और झड़प की घटना में खान सर के दो सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप लगा. पुलिस ने कदमकुआं थाने में हत्या के प्रयास (इठर की धारा 109) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया. इसके बाद रौशन आनंद (ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक) के पक्ष से जुड़े गौरव कुमार और अभिषेक कुमार समेत अन्य लोगों को भी मामले में शामिल किया गया. रौशन आनंद को खुद वैंडलिज्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 12 दिन बाद जमानत मिली.

वकीलों ने क्या कहा?

खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ह्यहमने कोर्ट से आज ही सुनवाई की मांग की थी, लेकिन विरोध के बाद कोर्ट ने समय दिया. हम 30 जून को पूरी तैयारी के साथ पेश होंगे.

क्रीमिया में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, रूस ने लगाई इमरजेंसी

मॉस्कोः रूस-यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक दौर में पहुंचता दिख रहा है. यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद रूस ने क्रीमिया और सेवस्तोपोल में क्षेत्रीय स्तर पर आपातकाल (स्टेट ऑफ इमरजेंसी) घोषित कर दिया है. वहीं रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस ने भी यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसे युद्ध में घसीटने की कोशिश की गई तो संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा. रूसी प्रशासन के मुताबिक हाल के दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया में ईंधन भंडार, तेल सुविधाओं और लॉजिस्टिक नेटवर्क को लगातार निशाना बनाया है. इससे कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो गया है, बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और पर्यटकों के लिए गर्मियों के कैंप तथा पर्यटन गतिविधियां सितंबर तक स्थगित कर दी गई हैं.

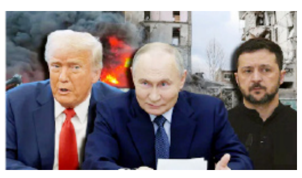

भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरूआत में भारत का दौरा कर सकते हैं . अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसको लेकर बड़ा संकेत दिया है . उन्होंने कहा कि ट्रंप की भारत यात्रा की दिशा में काम चल रहा है और उम्मीद है कि अगले साल की शुरूआत में यह दौरा हो सकेगा . क्शठर की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में भारत-अमेरिका संबंधों पर बात करते हुए रुबियो ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते शानदार दौर में हैं . उन्होंने बताया कि जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहद अच्छी मुलाकात हुई थी . दोनों देश अब व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं .

पहले भी आए है विनाशकारी भूकंप, 9.5 की तीव्रता से मची तबाही

नई दिल्ली। हाल ही में वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने एक बार फिर दुनिया को यह याद दिला दिया है कि प्रकृति की प्रचंड शक्तियों के सामने इंसान कितना असहाय है। इन झटकों ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया और अपने पीछे बबार्दी के निशान छोड़ गए। हालांकि ये भूकंप वेनेजुएला के इतिहास के सबसे बड़े झटकों में से हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों की सूची में इनका स्थान नहीं बन पाया है, जो हमें इतिहास के कुछ और भी विनाशकारी भूकंपों की याद दिलाता है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विश्व का सबसे शक्तिशाली दर्ज भूकंप वर्ष 1960 में दक्षिणी चिली के बायोबियो क्षेत्र में आया था। 9.5 तीव्रता वाले इस ग्रेट चिली भूकंप ने धरती को इस कदर हिलाया कि इसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा में करीब 1,655 लोगों की मौत हुई थी और बड़े पैमाने पर संरचनात्मक क्षति हुई, जिसके निशान दशकों तक महसूस किए गए। इस सूची में दूसरा सबसे बड़ा नाम वर्ष 1964 के अलास्का भूकंप का है, जिसकी तीव्रता 9.2 मापी गई थी। यह भूकंप लगभग चार मिनट तक महसूस किया गया, जिससे अलास्का और उसके आस-पास के इलाकों में भारी जान-माल का नुकसान हुआ। इस आपदा में लगभग 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

इतिहास की सबसे दर्दनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक वर्ष 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र में आया 9.1 तीव्रता का भूकंप था। समुद्र के भीतर आए इस महाविनाशकारी भूकंप ने भयानक सुनामी को जन्म दिया, जिसकी लहरों ने भारत सहित हिंद महासागर के कई तटीय देशों में भारी तबाही मचाई। इस त्रासदी में 2.8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जिससे यह आधुनिक इतिहास की सबसे घातक सुनामी आपदाओं में से एक बन गई। इसके बाद वर्ष 2011 में जापान के तोहोकू क्षेत्र में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप ने भी दुनिया को झकझोर दिया। इस भूकंप के बाद उत्पन्न हुई सुनामी ने जापान के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया और 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली, साथ ही फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के सुदूर कामचटका क्षेत्र में भी दो बड़े भूकंप दर्ज किए गए, जिनमें लगभग एक सदी का अंतर था। वर्ष 1952 में आए भूकंप की तीव्रता 9.0 थी, जिसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हुई। वहीं, वर्ष 1925 में इसी क्षेत्र में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं थी।

हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा देती है

भारत का नाम भी इस फेहरिस्त में शुमार है, आजादी के महज तीन साल बाद, वर्ष 1950 में अरुणाचल प्रदेश में आए 8.6 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें करीब 780 लोगों की मौत हुई। अन्य उल्लेखनीय भूकंपों में वर्ष 1906 में इक्वाडोर के एस्मेराल्डास क्षेत्र में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप शामिल है, जिसमें करीब 1,500 लोगों की जान गई थी। वर्ष 2010 में चिली के बायोबियो क्षेत्र में फिर से 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 523 लोगों की मौत हुई। जबकि वर्ष 1965 में अमेरिका के अलास्का में आए 8.7 तीव्रता के भूकंप में किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। ये घटनाएं हमें पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों की अप्रत्याशितता और विनाशकारी क्षमता की याद दिलाती हैं, जो हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा देती हैं।

सीएम फडणवीस के फोन पर बनी बात

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांडः उज्ज्वल निकम करेंगे सरकारी पैरवी

मुंबई। पुणे के लोहगढ़ किले से धक्का देकर की गई रियल एस्टेट डायरेक्टर केतन अग्रवाल की नृशंस हत्या के मामले में अब देश के दिग्गज वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले जैसे कई ऐतिहासिक मुकदमों में अपनी प्रभावी पैरवी से न्याय दिला चुके निकम इस हाई-प्रोफाइल केस में विशेष लोक अभियोजक की भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार दोपहर व्यक्तिगत रूप से उन्हें फोन किया और केतन अग्रवाल हत्याकांड के मुकदमों की कमान संभालने का आग्रह किया था। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उज्ज्वल निकम ने खुद इस बात का

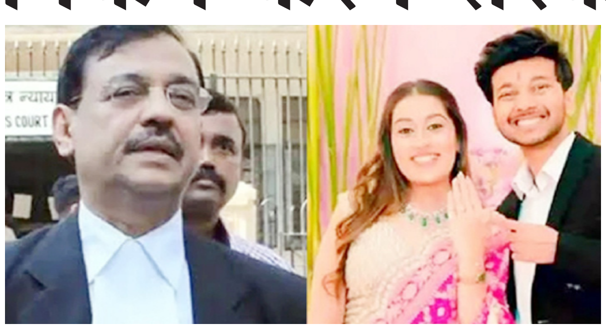

खुलासा किया। निकम ने बताया कि पुणे में मृतक केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले की पैरवी उनसे कराने की मांग की थी, जिसे सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

उज्ज्वल निकम ने कहा, शुक्रवार दोपहर मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फोन आया। पीड़ित परिवार ने उनसे मिलकर मेरी नियुक्ति का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने मुझे फोन पर इस केस के प्राथमिक तथ्यों से अवगत कराया और कहा कि यह वीभत्स हत्याकांड राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह पूरी तरह से एक सोची-समझी हत्या है। मुख्यमंत्री के विश्वास जताने के बाद मैंने इस केस के लिए अपनी मौखिक सहमति दे दी है। निकम की इस सहमति से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

केस की वर्तमान स्थिति और कानूनी बारीकियों पर बात करते हुए निकम ने बेहद नपा-तुला और रणनीतिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी इस मामले के सभी तथ्यों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं क्योंकि पुलिस अभी भी मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने अभी तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। मेरी वास्तविक भूमिका चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही शुरू होगी, इसलिए अभी जांच की प्रगति पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने आगे कहा, रिपोर्टों और प्राथमिक जानकारियों से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यह पूरा मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका हुआ है। ऐसे मामलों में कड़ियों को जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह मामला बेहद गंभीर है। शुरूआती तौर पर यह एक गहरी आपराधिक साजिश का मामला लग रहा है। हमें देखना होगा कि पुलिस किस तरह से तथ्यों को सामने लाती है और आरोपियों के खिलाफ अकाट्य सबूत जुटाकर उन्हें दोषी साबित करती है।

घर में पाल रखे थे 300 से ज्यादा विशाल अजगर, पुलिस देखकर हुई हैरान

अजगरों को बेच कर कमाता था मोटी रकम, पुलिस ने गिरफ्तार भेजा जेल

बीजिंग। चीन में एक व्यक्ति अपने घर में 300 से ज्यादा अजगर पाले हैं। मामला तब उजागर हुआ जब एक बुजुर्ग इंसान ने 2024 में एक पहाड़ी इलाके के पास एक विशाल अजगर देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसकी जानकारी से पुलिस के साथ-साथ लोग भी दंग रह गए। जांच शुरू होने के बाद जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को शुरूआती जांच में शक हुआ कि यह अजगर स्थानीय प्रजाति का नहीं है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जांच तेज की और उन घरों पर विशेष नजर रखी जहां असामान्य रूप से ज्यादा बिजली की खपत हो रही थी। इसी दौरान गुओ नामक इंसान पुलिस के शक के घेरे में आया। गुओ अकेले रहता था और उसके घर पर नियमित रूप से छोटे सफेद चूहों के पार्सल पहुंचते थे, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सांपों के भोजन के रूप में किया जाता है।

जानकारी के मुताबिक जब पुलिस ने गुओ के घर पर छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। घर के कई कमरों में प्लास्टिक के सैकड़ों डिब्बे रखे हुए थे और करीब हर डिब्बे में एक अजगर था। गुओ ने अपने रहने के लिए केवल एक कमरा रखा था, जबकि बाकी पूरा मकान सांपों के पालन-पोषण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने उसके घर से कुल 309 अजगर बरामद किए, जिन्हें बाद में सुरक्षित रूप से चिड़ियाघर में भेज दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि गुओ कई सालों से अजगरों की ब्रीडिंग कर रहा था और अब तक करीब 80 सांप बेच चुका था। पूछताछ में उसने बताया कि बचपन से ही उसे सांपों में विशेष रुचि थी। वह कई रंगों और पैटर्न वाले अजगर विकसित करने की कोशिश कर रहा था और उसे यह काम बेहद आकर्षक लगता था। मामले में दो अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आई। इनमें से एक व्यक्ति सांपों की बिक्री में उसकी मदद करता था, जबकि एक दुकान संचालक ने शुरूआती दौर में उसे अजगर उपलब्ध कराए थे।

सीजफायर तोड़ा तो भड़के ट्रंप, ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले

वॉशिंगटन। मिडिल ईस्ट में एक हफ्ता पहले ही संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन यह सहमति चंद दिनों में ही टूटती दिख रही है। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार, 26 जून को ओमान तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले का जवाब दिया और ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर भीषण जवाबी हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन केंद्रों के साथ-साथ तटीय रडार साइटों को निशाना बनाया है, जिसकी पुष्टि स्वयं अमेरिकी अधिकारियों ने की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इस हरकत को सीजफायर समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन करार दिया है और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।

25 जून को सिंगापुर के झंडे वाले एक बड़े मालवाहक जहाज पर ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकलते समय ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन दागे गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, इस जहाज को निशाना बनाकर कुल चार ड्रोन दागे गए थे, जिनमें से तीन को अमेरिकी सेना ने हवा में ही मार गिराया।

रामायण के राम- प्रभु राम खुद करेंगे चंदा चोरी का हिसाब ?

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें अपने चरम पर हैं, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि अगले सप्ताह मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है।

इस संभावित फेरबदल में जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, वे हैं मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल और पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। अरुण गोविल, जिन्हें टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर देश भर में पहचान मिली थी, उनकी कैबिनेट में एंट्री की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी का मुद्दा बुरी तरह गरमाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले प्रभु राम (अरुण गोविल)

खुद अपने चंदे की चोरी से हुए राजनीतिक नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आ रहे हैं?

2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, राम मंदिर में दान चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से रामभक्तों के बीच जा रहे गलत संदेश को रोकने के लिए बीजेपी को एक बेदाग और बड़े चेहरे की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। मेरठ से सांसद अरुण गोविल की कैबिनेट में संभावित एंट्री को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अरुण गोविल भारतीय जनमानस में केवल एक सांसद या अभिनेता ही नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए वह भगवान राम का साक्षात स्वरूप और अगाध श्रद्धा का केंद्र हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी साफ-सुथरी और प्रभु राम वाली छवि का इस्तेमाल पार्टी यूपी में डैमेज कंट्रोल के लिए कर सकती है, जिससे यह नैरेटिव स्थापित किया जा सके कि राम के काम में गड़बड़ी करने वालों का हिसाब खुद राम के प्रतिनिधि करेंगे।गोविल को कैबिनेट में लाने की रणनीति सिर्फ अयोध्या के डैमेज कंट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से गहराई से जुड़े हैं।

साबित हो सकता है

अरुण गोविल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मेरठ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। उन्हें मंत्री पद से नवाजने से एक तीर से दो निशाने लगेंगे झ पहला, अवध (अयोध्या) क्षेत्र में रामभक्तों के आक्रोश पर मरहम लगेगा और दूसरा, पश्चिमी यूपी में भी पार्टी का आधार मजबूत होगा। पिछले चुनावों में विपक्षी गठबंधन (सपा-कांग्रेस) ने जिस तरह से बीजेपी के वोटबैंक में सेंध लगाई थी, उसकी भरपाई के लिए गोविल जैसा पैन-यूपी और सर्वमान्य हिंदुत्ववादी चेहरा पार्टी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है।

पृथ्वी तो घूम रही लगातार, फिर भूकंप क्यों आता है ?

पृथ्वी का घूर्णन और भूकंप दो अलग प्रक्रियाएं; टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से हिलती है धरती

नई दिल्ली। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर आने वाले भूकंप अक्सर बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तब हमें उसका कोई झटका क्यों महसूस नहीं होता, जबकि भूकंप के समय धरती अचानक हिलने लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का घूमना और भूकंप आना दो अलग-अलग प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है।

वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी लगभग 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन इसकी गति लगातार और समान रहती है। चूंकि हम, वातावरण और पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुएं उसी गति से एक साथ घूम रही हैं, इसलिए हमें इसका कोई झटका महसूस नहीं होता। इसे हवाई जहाज के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब विमान एक समान गति से उड़ता रहता है, तो यात्रियों को उसकी रफ्तार महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही विमान की गति बदलती है या झटका लगता है, तब लोग उसे महसूस करते हैं। पृथ्वी के साथ भी यही स्थिति होती है।

टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से आता है भूकंप

भूकंप का वास्तविक कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां हैं। पृथ्वी की बाहरी परत कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जो लगातार बेहद धीमी गति से खिसकती रहती हैं। इन प्लेटों के नीचे स्थित अर्ध-द्रव अवस्था वाली मेंटल परत के कारण प्लेटों में लगातार हलचल बनी रहती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं या अचानक खिसक जाती हैं, तो उनमें लंबे समय से जमा ऊर्जा अचानक मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है और धरती कांपने लगती है।

छोटे और बड़े भूकंप में अंतर

विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन दुनिया में हजारों छोटे भूकंप आते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश इतने कमजोर होते हैं कि लोगों को उनका पता भी नहीं चलता। जब प्लेटों के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तब शक्तिशाली भूकंप आते हैं। ऐसे भूकंप इमारतों को गिरा सकते हैं, सड़कों और जमीन में दरारें पैदा कर सकते हैं तथा बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि का कारण बन सकते हैं।

रिक्टर स्केल से मापी जाती है तीव्रता

भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह पैमाना भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को दशार्ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार रिक्टर स्केल पर प्रत्येक एक अंक की वृद्धि ऊर्जा में लगभग दस गुना बढ़ोतरी को दशार्ती है। इसी कारण 6 तीव्रता का भूकंप, 5 तीव्रता के भूकंप की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी साबित हो सकता है।

कई चरणों में महसूस होते हैं झटके

विशेषज्ञ बताते हैं कि भूकंप अक्सर केवल एक झटके तक सीमित नहीं रहता। कई बार मुख्य भूकंप से पहले छोटे कंपन महसूस होते हैं, जिन्हें अग्र झटके कहा जाता है। इसके बाद मुख्य भूकंप आता है और फिर कुछ समय तक बाद के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। कुछ पशु-पक्षी इन शुरूआती कंपन को मनुष्यों से पहले महसूस कर लेते हैं। इसलिए उनके असामान्य व्यवहार को कई बार प्राकृतिक चेतावनी संकेत के रूप में देखा जाता है।

भूकंप के दौरान क्या करें

भूकंप के समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। विशेषज्ञों के अनुसार झटके महसूस होते ही खुले और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करना चाहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कांच, भारी वस्तुओं तथा कमजोर दीवारों से दूर रहना चाहिए। यदि बाहर निकलना संभव न हो तो मजबूत मेज या डेस्क के नीचे शरण लेना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जागरूकता, आपदा प्रबंधन और भूकंपरोधी निर्माण तकनीकों के जरिए इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

16-19 तक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बदले रूट से आएगी

रायपुर। झाँसी मंडल के ललितपुर स्टेशन में यार्ड रिमाडलिंग का कार्य की वजह से 16 से 19 जुलाई तक 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन उन 4 दिनों तक व्हाया मथुरा-बयाना-कोटा-नागदा-संत हिरदाराम नगर-भोपाल मार्ग होकर बिलासपुर आयेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 08407 भुवनेश्वर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) के मध्य 26 जून, 2026 को भुवनेश्वर से 23 बजे रवाना होकर 23.35 बजे नाराज मर्थापुर, 00.36 बजे डेकेनाल, 1:50 बजे तालचेर रोड 02.05 बजे अंगुल, 04.40 बजे संबलपुर, 5:40 बजे बरगढ़ रोड, 6:43 बजे बलांगीर 7:50 बजे टिटलागढ़, 8:50 बजे कांटाबाजी, 09.52 बजे खरियार रोड, 10:50 बजे महासमुंद रोड, 12:55 बजे रायपुर, 14 बजे दुर्ग, 16.00 बजे गोंदिया, 18.20 बजे नागपुर, 21:30 बजे बडनेरा, 22.28 बजे अकोला, 00.35 बजे भुसावल, 04.40 बजे नासिक, 07 बजे कल्याण होते हुए 28 जून 2026 को 9 बजे एलटीटी) पर पहुंचेगी। अतिरिक्त एसी-3 कोच 18030/18029 शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा 27 जून से 03 जुलाई तक तथा 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में 29 जून से 05 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी।

नैनो उर्वरक के प्रयोग से युवा किसान पुनम की खेती बनी लाभकारी

रायपुर। कोंडागांव जिले के ग्राम ग्राम दावड़ीबेड़ा (चिखलपुटी) के युवा किसान पुनम नेताम आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। उन्होंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग कर अपनी फसलों में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया है। पिछले दो वर्षों से वे धान, मक्का और सब्जियों की खेती में नैनो उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुनम नेताम ने बताया कि गत वर्ष उन्होंने 10 एकड़ भूमि में मक्का की खेती की थी। नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसल की वृद्धि अच्छी हुई और उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। उनका कहना है कि नैनो उर्वरक का छिड़काव सीधे पौधों की पत्तियों पर किया जाता है, जिससे पोषक तत्व शीघ्रता से पौधों तक पहुंचते हैं। इससे उर्वरक की उपयोग क्षमता बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत, पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने किया सियान गुड़ी का अवलोकन

रायपुर। जशपुर जिले के भागलपुर रोड स्थित डे-केयर सेंटर सियान गुड़ी का छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरां से आए वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय की मंशानुरूप संचालित यह केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, देखभाल और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल के रूप में विकसित हो रहा है। मैदानी प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ आत्मीय संवाद कर उनके जीवन अनुभवों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को करीब से समझा। इस दौरान उन्हें प्रशासनिक दायित्वों के साथ मानवीय संवेदनशीलता, जनसेवा और जरूरतमंद नागरिकों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर मिला। प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर रविशंकर वर्मा, सुश्री निधि प्रधान, सुश्री नंदनी साहू, मनीष बघेल, सौरभ दीवान, लखेश्वर यादव एवं सत्येन्द्र कुमार बंजारे ने केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने रेडियो, टेलीविजन, कैरम, लूडो सहित अन्य इनडोर खेलों, पुस्तकालय, धार्मिक एवं प्रेरणादायी पुस्तकों, योग, फिजियोथेरेपी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली।

दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिली 1 करोड़ 20 लाख की आर्थिक सहायता

धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सैलरी पैकेज संबंधी एमओयू किए गए हैं।

इन एमओयू के अंतर्गत पुलिस कर्मियों को विभिन्न वित्तीय एवं बीमा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो सके।

इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा सैलरी पैकेज के अंतर्गत प्रदत्त बीमा सुविधा का लाभ तीन दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को प्रदान किया गया।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार एवं एसबीआई के शाखा प्रबंधक चेतन सिंह ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत पुलिस कर्मियों के नामांकित आश्रितों को बीमा दावा राशि के चेक वितरित किए गए।

इस दौरान जिला दुर्ग में पदस्थ रहे दिवंगत आरक्षक रामेश्वर नेताम,जिनका परिवार वर्तमान में धमतरी जिले के ग्राम करेगांव में निवासरत है, की नामिनी डामिन बाई को 01 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि का चेक प्रदान किया गया।

इसी प्रकार दिवंगत आरक्षक कांतू ठाकुर, जिला धमतरी की नामिनी राम बाई ठाकुर को 10 लाख रुपये की बीमा राशि के चेक प्रदान किए गए,ऐसे ही दिवंगत आरक्षक धनेश देवांगन,जिला धमतरी की नामिनी नेहा देवांगन को 10 लाख रुपये की बीमा राशि के चेक प्रदान किए गए।

इस प्रकार कुल तीनों परिवार के नामिनी को 1 करोड़ 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि पुलिस विभाग केवल अपने कर्मचारियों के साथ ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के सुख-दुख में भी सहभागी रहता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा किए गए ऐसे कल्याणकारी प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी पुलिस कर्मी के आकस्मिक निधन की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि पुलिस परिवारों के प्रति विभाग एवं संस्थानों की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एसपी ने उपस्थित परिजनों से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि धमतरी पुलिस हर परिस्थिति में पुलिस परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को सुरक्षा एवं विश्वास प्रदान करती हैं। एसबीआई शाखा प्रबंधक चेतन सिंह ठाकुर ने बताया कि बैंक द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध सैलरी पैकेज में कई महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं, जिनमें बीमा सुरक्षा प्रमुख है। उन्होंने कहा कि बैंक भविष्य में भी पुलिस परिवारों को बेहतर सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम साय ने कहा- अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मंडल

सीजीएचआईडीबी के नए लोगो का विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नए लोगो का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में आवास बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रा के माध्यम से कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सहित विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का नया लोगो तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि ढाई लाख रुपए का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों और वायदों को तेजी से पूरा किया है। सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद साढ़े दस लाख से अधिक परिवार के आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 नए आवास तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से 15 हजार अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए गए हैं तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी विशेष आवास योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'सेवा सेतु' के माध्यम से 450 से अधिक शासकीय सेवाएं अब मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 भी प्रारंभ की गई है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 65 हजार घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से सरकार घर में सोलर संयंत्र लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी भी दे रही है और इन परिवारों लिए आने वाले समय में बिजली पूरी तरह मुफ्त हो जाएगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच पाएंगें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से लंबित बिजली बिल के भुगतान का भी बड़ा अवसर दिया है और बिल पर लगने वाले सरचार्ज समेत आकर्षक छूट का प्रावधान किया है। साय ने कहा कि सरकार न केवल जनहितैषी योजनाएं लागू कर रही है बल्कि सुशासन तिहार के माध्यम से उसका फीडबैक लेने लोगों के बीच भी गई। दो महीने लगातार जनता से फीडबैक लेकर व्यवस्थाओं में सुधार का काम किया गया है। उन्होंने इस दौरान शासन की विभिन्न नवाचारी पहल की जानकारी देते हुए सुशासन और पारदर्शी सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर वर्षों से लंबित संपत्तियों के विक्रय को गति दी तथा वित्तीय अनुशासन स्थापित किया।

सीएम साय ने कार्यक्रम को किया संबोधित

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होने का सपना होता है और राज्य सरकार इस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केवल गृह निर्माण तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आर्थिक चुनौतियों से उबरते हुए मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडल के अध्यक्ष तथा पूरी टीम को बधाई दी।

मंत्री ओ.पी. चौधरी ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभाग में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल को अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में नई पहचान देकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में इसकी भूमिका का विस्तार किया गया है। मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय करने वाले विभागों को वित्तीय और मानव संसाधन के माध्यम से सक्षम बनाने का काम किया है ताकि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ सके।

सीएम साय करेंगे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित

रायपुर। देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस माने जाने वाले 25 जून 1975 को लगाये गये आपातकाल की स्मृति को जीवित रखने तथा नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस तथा 26 जून को आपातकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

लोकतंत्र प्रहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि 26 जून 1975 से मार्च 1977 तक चल 21 माह के आपातकाल को देश कभी मूल नहीं कर सकता उस कालखंड में नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया गया एवं हजारों लोकतंत्र समर्थकों को मीसा अन्य कठोर कानूनों के अत्तर्गत जेलों में बद किया गया तथा प्रस की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए गए। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया।

उपासने ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 28 जून को प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोजित भव्य सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा साथ ही इस अवसर पर आपातकाल मोड़ा सदर्भ ग्रंथ स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा।

विशेष आकर्षण यह होगा की लोकतंत्र सेनानी राघ व प्रहरी के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर प्रदेश स्तर की आपातकाल कभी विस्मृत न हो एवं 25 जून संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता इन विषयों पर निका प्रतियोगिता आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा विजयी प्रथम द्वितीय तृतीय चयनित छात्रों को विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर 31000, 21000 व 11000 रुपए नगद पुरस्कार दोनों स्तरों पर गय स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा।

उसी प्रकार सनी 520 शामिल विद्यार्थियों सहित विद्यालय व महाविद्यालय के प्राचार्य को भी मुख्यमत्री द्वारा 28 जून को सम्मानित किया जाएगा इस वर्ष भी इस भव्य आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया जा रहा है यह भव्य आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 28 जून रविवार को 11:00 बजे से आयोजित है।

सम्मेलन में संगठन के समस्त पदाधिकारी व प्रबुद्ध वैचारिक सत्त्वाओं, मंत्रियों, विधायकों, निगम आयोग अध्यक्षली सहित बड़ी संख्या में शुभ चितकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में आपातकाल का काला इतिहास एवं संविधान हत्या दिवस विषय पर प्रयुद्ध पत्काओं क व्याख्यान भी होगे तथा इस विषय पर प्रकाशित विशेष स्मारिका आपातकाल योद्धा का विमोचन किया जाएगा।

अभनपुर में पहला विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला

367 ग्रामीणों का हुआ मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, योग के तरीके बताए गए

रायपुर। अभनपुर विकासखंड के बेलर गांव में गुरुवार को पहला विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में हुए इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। शिविर का शुभारंभ सरपंच शीलादेवी टंडन, चंद्रशेखर टंडन और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भगवान धन्वंतरि के चित्र पर दीप जलाकर किया गया। शिविर प्रभारी डॉ. विनीता सोनवानी ने बताया कि शिविर में 367 लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मरीजों को डॉक्टरों ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी और जरूरत के अनुसार दवाइयां भी दी गईं। इसके अलावा 211 लोगों का ब्लड प्रेशर और 63 लोगों का ब्लड शुगर जांचा गया। रोगों से बचाव और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 150 लोगों को आयुष क्वाथ वितरित किया गया। शिविर में आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ दिनचर्या, मौसम के अनुसार खान-पान और योग के फायदे भी सरल भाषा में समझाए गए। योग प्रशिक्षक भुवनेश्वरी साहू ने ग्रामीणों को आसान योगासन और नियमित योग करने के तरीके बताए। साथ ही स्वास्थ्य और योग से जुड़े जानकारी वाले ब्रोशर भी बांटे गए, ताकि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें अपना सकें। शिविर को सफल बनाने में डॉ. शीतला देवी चौहान, डॉ. शशि भूषण तिवारी, डॉ. डोलानारायण पटेल, डॉ. दीप्ति श्रीवास, डॉ. अंकिता पटेल, चोवा राम साहू, हेमंत कुमार मेंश्राम, तोषण साहू, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पुष्पा सोनवानी, शैलेन्द्र देवांगन, अंकित हलधर और डेमन यादव ने सहयोग दिया।

8 लोगों की संदिग्ध मौत, तंत्र विद्या की आशंका

कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने गृहमंत्री से की सीबाईआई जांच की मांग

रायपुर। रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी अभी भी बनी हुई है। 21 डॉक्टरों को प्रोफेसर बनाया गया है, लेकिन इनमें से 17 का दूसरे मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में पहले से टीचर की कमी झेल रहे कॉलेज में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में टीचर के कुल 417 पद मंजूर हैं। इनमें से 166 पद खाली हैं। अभी 251 डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। इनमें 156 रेगुलर और 95 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में टीचर कम होने का सीधा असर पीजी की सीटों और पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ता है। 2025 में सर्जरी विभाग में टीचर कम होने की वजह से पीजी की 2 सीटें घटानी पड़ी थीं। सिर्फ रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में भी यही हाल है। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक सरकारी डेंटल कॉलेज में टीचर के 1,934 पद मंजूर हैं, लेकिन 985 पद खाली हैं। यानी करीब 51त्न पदों पर डॉक्टर नहीं हैं।रायपुर के डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल और बिलासपुर के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भी 139 मंजूर पदों में से 81 खाली हैं। यानी यहां करीब 58त्न डॉक्टरों की कमी है। लंबे समय से रेगुलर भर्ती नहीं होने की वजह से मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई और अस्पतालों की सेवाएं दोनों प्रभावित हो रही हैं। पिछले करीब ढाई साल में आंबेडकर अस्पताल और डीकेएस अस्पताल से 100 से ज्यादा डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं। रेगुलर नौकरी नहीं मिलने से कई डॉक्टर मध्यप्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में चले गए। प्रोफेसर बनने के बाद जिन डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ है, वे फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, गायनिक, ईएनटी, सर्जरी, दंतरोग, एनेस्थीसिया, चर्म रोग और रेडियोथेरेपी विभाग से हैं। इन्हें कवर्धा, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर और बिलासपुर के मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया है।

पहले ही 166 पद खाली थे, अब मुश्किलें और बढ़ी; 21 डॉक्टर प्रोफेसर बने

रायपुर मेडिकल कॉलेज के 17 टीचर्स का ट्रांसफर

रायपुर। रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी अभी भी बनी हुई है। 21 डॉक्टरों को प्रोफेसर बनाया गया है, लेकिन इनमें से 17 का दूसरे मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में पहले से टीचर की कमी झेल रहे कॉलेज में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में टीचर के कुल 417 पद मंजूर हैं। इनमें से 166 पद खाली हैं। अभी 251 डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। इनमें 156 रेगुलर और 95 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में टीचर कम होने का सीधा असर पीजी की सीटों और पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ता है। 2025 में सर्जरी विभाग में टीचर कम होने की वजह से पीजी की 2 सीटें घटानी पड़ी थीं। सिर्फ रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में भी यही हाल है। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक सरकारी डेंटल कॉलेज में टीचर के 1,934 पद मंजूर हैं, लेकिन 985 पद खाली हैं। यानी करीब 51त्न पदों पर डॉक्टर नहीं हैं।रायपुर के डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल और बिलासपुर के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भी 139 मंजूर पदों में से 81 खाली हैं। यानी यहां करीब 58त्न डॉक्टरों की कमी है। लंबे समय से रेगुलर भर्ती नहीं होने की वजह से मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई और अस्पतालों की सेवाएं दोनों प्रभावित हो रही हैं। पिछले करीब ढाई साल में आंबेडकर अस्पताल और डीकेएस अस्पताल से 100 से ज्यादा डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं। रेगुलर नौकरी नहीं मिलने से कई डॉक्टर मध्यप्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में चले गए। प्रोफेसर बनने के बाद जिन डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ है, वे फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, गायनिक, ईएनटी, सर्जरी, दंतरोग, एनेस्थीसिया, चर्म रोग और रेडियोथेरेपी विभाग से हैं। इन्हें कवर्धा, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर और बिलासपुर के मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया है।

थर्ड जेण्डर के लिए जॉब का मौका सिक्योरिटी गार्ड पदों पर सीधी भर्ती

2 जुलाई को रायपुर में इंटरव्यू, सभी जिलों के उम्मीदवार होंगे पात्र

रायपुर. थर्ड जेंडर के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग 2 जुलाई को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करेगा। इंटरव्यू रायपुर के संबल केंद्र, आईडीएसएमटी बिल्डिंग, महंत कॉलेज के पास गांधी चौक में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर चयन करेगी। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के तृतीय लिंग समुदाय के पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न जिलों में की जाएगी।

आवश्यक डाक्यूमेंट्स साथ लाना होगा

आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य तृतीय लिंग समुदाय को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से अधिक से अधिक संख्या में वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होने की अपील की है।

महत्वपूर्ण ख़बर

फुटबॉल वर्ल्ड कप में बना सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड, 2022 में कतर में हुए वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड टूटा

- ईस्ट रदरफोर्ड (अमरीका)। अमरीका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार को गोलों का नया रिकॉर्ड बन गया है। टूर्नामेंट में अब तक कुल 177 गोल हो चुके हैं, जो किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं।इससे पहले सबसे ज्यादा 172 गोल का रिकॉर्ड कतर में खेले गए 2022 वर्ल्ड कप में बना था। मौजूदा संस्करण में यह रिकॉर्ड ग्रुप चरण के दौरान ही टूट गया। इस बार पहली बार 48 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं। टूर्नामेंट में शुक्रवार 26 जून को छह मैच खेले गए।

निकोलस पेपे के डबल गोल से आइवरी कोस्ट ने ग्रुप-ई मैच में कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट में जगह बना ली। अब आइवरी कोस्ट 30 जून को राउंड ऑफ-32 में ग्रुप आई की उपविजेता टीम (फ्रांस या नॉर्वे) से भिड़ेगा। 24वीं रैंक की टीम इक्वाडोर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में शुक्रवार को चार बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हरा दिया है।

विम्बलडन में माया जॉइंट से पहला मुकाबला खेलेंगी सेरेना

लंदन। सोमवार से शुरू हो रहे विम्बलडन टेनिस टूनामेंट से खेल में वापसी कर रही अमेरिका की 42 साल की अनुभवी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की 20 साल की माया जॉइंट से खेलेंगी। चार साल बार वापस कर रही सेरेना का मुकाबला देखने को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। सात बार की विम्बलडन एकल चैंपियन रही सेरेना ने साल 2022 में खेल से संन्यास ले लिया था। अब लगभग चार साल के लंबे अंतराल के बाद विम्बलडन में वह उतर रही हैं।

सेरेना को इस टूनामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है। एकल के अलावा, वह अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स के साथ युगल स्पर्धा में भी हिस्सा लेंगी, जहां विलियम्स बहनों की जोड़ी एक बार फिर खेलती दिखेगी। सेरेना ने अपनी वापसी की शुरूआत दो युगल अभ्यास मुकाबलों से की थी, जिससे उनकी फिटनेस और खेल लय का संकेत मिला था। रविवार को ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा उनके एकल खेलने की आधिकारिक घोषणा ने उनकी वापसी को पक्का कर दिया। गौरतलब है कि सेरेना ने अपना पिछला एकल मुकाबला 2022 के यूएस ओपन में खेला था, जहाँ उन्हें तीसरे दौर में अजला टोमल्यानोविच के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि वह टेनिस से दूर होकर अपने जीवन के एक नए चरण की ओर बढ़ रही हैं। यह नया चरण उनके परिवार के लिए समर्पित रहा है, और 2023 में उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद यह समझा जा रहा था कि उनका पेशेवर करियर शायद अब समाप्त हो गया है। हालांकि, विम्बलडन में उनकी वापसी ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।विम्बलडन में सेरेना ने अपना पिछला मुकाबला भी 2022 में खेला था, जहाँ उन्हें अप्रत्याशित रूप से पहले दौर में तत्कालीन विश्व नंबर 115 हार्मनी टैन ने पराजित कर दिया था। इस बार, वह एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ कोर्ट में उतरेंगी।

फीफा विश्वकप ट्रॉफी में लगे सोने की कीमतें दोगनी हुई

न्यूजर्सी। हाल के कुछ समय में जिस प्रकार से सोने की कीमतों में उछाल आया है। उसका प्रभाव फीफा विश्वकप ट्रॉफी पर भी पड़ा है। इसी कारण फीफा विश्वकप ट्रॉफी में लगे सोने की कीमत अब बढ़कर लगभग 7.13 लाख डॉलर (तकरीबन 6.73 करोड़ रुपये) तक पहुंच गयी ये चार साल पहले की तुलना में दोगुना से भी अधिक है। वित्तीय आंकलन वाली एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के विश्व कप के समय ट्रॉफी में मौजूद सोने का मूल्य लगभग 2.77 लाख डॉलर आंका गया था। यह आंकड़ा दिखाता है कि केवल दो साल में सोने की कीमत में तेजी आई है। गौरतलब है कि फीफा विश्व कप ट्रॉफी 18 कैरेट सोने से बनी है और इसका कुल वजन 6.175 किलोग्राम है। इसमें लगभग 4.93 किलोग्राम सोना जड़ा है। इसी कारण ये सबसे कीमती ट्रॉफी मानी जाती है।

सोने की कीमतों में यह उछाल भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता को माना जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए विश्व कप ट्रॉफी का महत्व अमूल्य है, पर इसमें मौजूद सोने का मौद्रिक मूल्य इस बात का प्रमाण है कि इस कीमती धातु की कीमत पिछले कुछ साल में कितनी तेजी से बढ़ी है। इससे पहले 1974 के विश्व कप से पहले वर्तमान ट्रॉफी डिजाइन को पेश किया गया था, तब इसमें लगे सोने की अनुमानित कीमत केवल 25,000 डॉलर थी। यह तुलना सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल को दिखाती है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी दुनिया की उन कुछ प्रमुख खेल ट्रॉफियों में से एक है जो पूरी तरह से सोने से बनी है।

यह विशेषता इसे अन्य प्रतिष्ठित ट्रॉफियों से अलग करती है जबकि यूईएफए चैंपियंस लीग और यूईएफए यूरोपा लीग की ट्रॉफियां चांदी से बनी हैं, जिनकी धातु-आधारित कीमत क्रमशः लगभग 16,950 डॉलर और 22,600 डॉलर है। इसके अलावा अमेरिका में इंडियानापोलिस 500 मोटर रेसिंग प्रतियोगिता के विजेता को दी जाने वाली बोर्ग-वार्नर ट्रॉफी भी चांदी से बनी है और 69 किलोग्राम वजन के साथ इसकी अनुमानित धातु कीमत 1.56 लाख डॉलर है।

भारत-इंग्लैंड टी-20 सीरीजः कोल्स से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान

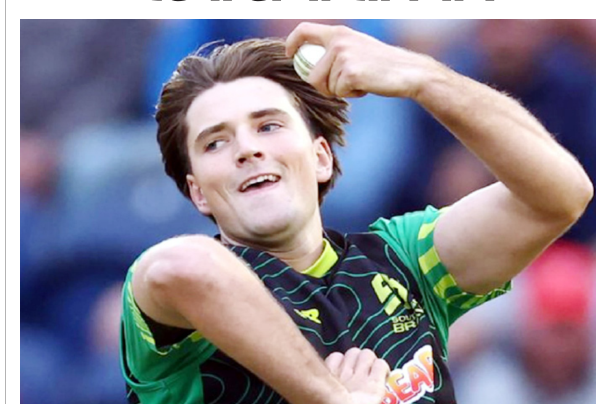

लंदन। भारतीय क्रिकेट टीम को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से होने वाली टी20 सीरीज में युवा खिलाड़ी जेम्स कोल्स से सावधान रहना होगा। भारतीय टीम इस दौरे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड की टीम में इस बार नये खिलाड़ी के तौर पर केवल कोल्स को रखा गया है। कोल्स दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं और स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। वह घरेलू क्रिकेट में पिछले एक साल से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस साल की शुरूआत में द हंड्रेड नीलामी में उन्होंने सदर्न ब्रेव की ओर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें टीम ने सबसे अधिक कीमतों में खरीदा था। हाल ही में ससेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप के एक मैच में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए इस युवा ने नाबाद 224 रन की शानदार पारी खेली थी। इस क्रिकेटर ने काउंटी के अलावा इस साल की शुरूआत में एसए 20 लीग में काव्या मारन की मालिकाना अधिकार वाली सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए भी खेला था जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। इंग्लैंड पुरुष टीम के मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कोल्स की जमकर सराहना की है। नॉर्थ ने कहा कि जेम्स कोल्स एक शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने इंग्लैंड लायंस के साथ-साथ देश-विदेश की टी-20 प्रतियोगिताओं में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है।

कोल्स का क्रिकेट करियर काफी प्रभावशाली रहा है, भले ही वह अभी युवा हैं। ससेक्स के लिए खेलते हुए, उन्होंने अब तक 58 फर्स्ट-क्लास, 24 लिस्ट-ए और 71 टी-20 मैच खेले हैं। सबसे छोटे प्रारूप टी-20 में, उन्होंने 61 पारियों में 146.37 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 1,373 रन बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। गेंदबाजी में भी, उन्होंने 56 पारियों में 59 विकेट लेकर अपनी ऑलराउंड क्षमता साबित की है।

हिमाचल की उड़नपरी सीमा का गोल्डन धमाका, नेशनल चैंपियनशिप में जीता सोना

चंबा। जिला चंबा की अंतरराष्ट्रीय धाविका उड़नपरी सीमा ने एक बार फिर देश भर में चंबा नाम गर्व से ऊंचा किया है। सीमा ने 24 से 28 जून तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 5000 मीटर की दौड़ 16:11:04 में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। बताते चलें कि यह भारत की सबसे बड़ी ट्रैक प्रतियोगिता होती है और यहीं से एशियन गेम्ज के लिए चयन होता है। एशियन गेम्ज में चयन के लिए सीमा ने फॉरेन रेस में पांच हजार मीटर की दौड़ में पहले ही टाइमिंग क्वॉलिफाई कर ली थी, लेकिन इस प्रतियोगिता में पहला स्थान लेने के बाद ही एशियन गेम्स के लिए चयन होना था। इसलिए एशियन गेम्स के लिए अब सीमा का चयन हो गया है। अभी 28 जून को इसी प्रतियोगिता में 10 हजार मीटर की दौड़ में भी सीमा भाग लेंगी।

टी20 ब्लास्ट 2026 के लिए घरेलू खिलाड़ी के तौर नॉट्स आउटलॉज टीम से खेलेंगे आमिर

लंदन। विवादों में रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब टी20 ब्लास्ट 2026 के बाकी बचे मैचों के लिए घरेलू खिलाड़ी के तौर पर नॉट्स आउटलॉज टीम से खेलेंगेहैं।

आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद ही घरेलू खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। इससे अब ये तेज गेंदबाज अपने क्रिकेट करियर की नई पारी शुरू कर रहा है। आमिर को एक समय पाक का एक बेहतरीन तेज गेंदबाज माना जाता था पर स्पॉट फिक्सिंग मामले के चलते उन्हें झटका लगा और पाक क्रिकेट में उनका करियर समय से पहले ही समाप्त हो गया। वहीं अब ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद आमिर का काउंटी क्रिकेट में विदेशी खिलाड़ी के वर्ग में नहीं गिना जाएगा जिससे इंग्लैंड की ओर से उनके पास अब घरेलू क्रिकेट में भी खेलने के कई अवसर हैं। नॉटिंघमशायर ने आमिर के साथ करार किसे जाने को सही बताया है। साथ ही कहा कि 34 वर्षीय आमिर ब्लास्ट अभियान के बाकी बचे मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे जिसमें नॉकआउट चरण भी शामिल है। काउंटी टीम अभी नॉर्थ ग्रुप में शीर्ष के करीब है और उन्हें उम्मीद है कि आमिर का लंबा अनुभव खिताब जीतने की उनकी संभावनाओं को और मजबूत करेगा।

क्लब ने कहा कि अब जब उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है। उन्हें विदेशी खिलाड़ी नहीं माना जाएगा। गौरतलब है कि आमिर का करियर सबसे उतार-चढ़ाव भरा रहा है। सा 2009 टी20 विश्व कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके नाम 364 टी20 मैचों में 425 विकेट लिए जिसमें उनका औसत 22.63 और इकॉनमी रेट 7.36 रहा।

कारोबार

अनिल अंबानी व रिलायंस इंफ्रा को सेबी से झटका; विदेशी मुद्रा भंडार 96.3 करोड़ डॉलर बढ़ा

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की उस सेटलमेंट अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी के करीब 6,526 करोड़ के कथित दुरुपयोग मामले को निपटाने की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक, यस बैंक निवेश मामले के बाद यह दूसरा मौका है, जब सेबी ने अनिल अंबानी की अर्जी खारिज की है। सेबी ने सितंबर 2025 में जारी अंतरिम आदेश में कहा था कि रिलायंस इंफ्रा के धन का उपयोग कुछ इस तरह किया गया कि अनिल अंबानी से जुड़े पक्षों को लाभ पहुंचने की आशंका है। रिलायंस इंफ्रा ने इंजीनियरिंग फर्म सीएलई प्राइवेट लि. के लिए लगभग 6,526 करोड़ के एक्सपोजर की जानकारी दी थी और उसे स्वतंत्र कंपनी बताया था। सेबी का आरोप है कि 2024 तक रिलायंस इंफ्रा ने कुल 17,670 करोड़ रुपये सीएलई को ट्रांसफर किए। बाद में सीएलई ने करीब 11,200 करोड़ अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों में निवेश किए।

विदेशी मुद्रा भंडार 96.3 करोड़ डॉलर बढ़ा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार 19 जून को समाप्त सप्ताह में 96.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 672.58 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में 9.98 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह 671.62 अरब डॉलर पर आ गया था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां घटकर 541.21 अरब डॉलर रह गईं। बीते सप्ताह स्वर्ण भंडार में तेज बढ़त हुई। इसका मूल्य 4.11 अरब डॉलर बढ़कर 107.93 अरब डॉलर हो गया।

कच्चा तेल 10 फीसदी साप्ताहिक गिरावट के करीब

होर्मुज में टैंकरों की आवाजाही सामान्य होने पर मंडरा रहे नए खतरों के बीच शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 3 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों बेंचमार्क इस सप्ताह लगभग 10 फीसदी की साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ते दिखे। ब्रेंट क्रूड 2.58 डॉलर यानी 3.43 फीसदी गिरकर 72.68 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि डब्ल्यूटीआई का भाव 2.50 डॉलर यानी 3.48 फीसदी टूटकर 69.42 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

फॉक्सवैगन में एक लाख कर्मियों की छंटनी की तैयारी

यूरोप की सबसे बड़ी वाहन निमार्ता कंपनी फॉक्सवैगन लागत कम करने और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए करीब एक लाख कर्मचारियों की छंटनी करने और जर्मनी में चार उत्पादन संयंत्र बंद करने की योजना पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ओलिवर ब्लूम ने प्रबंधन बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा। इसे अगले महीने कंपनी के सुपरवाइजरी बोर्ड के सामने चर्चा के लिए रखा जाएगा। वर्तमान में फॉक्सवैगन समूह में करीब 6.57 लाख कर्मचारी हैं। पुनर्गठन योजना के तहत कंपनी इस दशक के अंत तक 11 अरब यूरो (करीब 12.5 अरब डॉलर) की अतिरिक्त लागत घटाना चाहती है। इसके अलावा जर्मनी के नेकारसुल्म स्थित ऑडी संयंत्र तथा फॉक्सवैगन के हनोवर, ज्विकाउ और एमडेन संयंत्रों को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। कंपनी अपने कंपोनेंट्स कारोबार और फॉक्सवैगन ब्रांड के ढांचे में भी बदलाव कर सकती है।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात शुल्क घटने की संभावना

पश्चिम एशिया संकट थमने और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ने से अब इन पर लगे निर्यात शुल्कों में बदलाव हो सकता है। सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की मौजूदा दरें 30 जून तक लागू हैं। एक जुलाई को नई दरें घोषित होंगी। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने डीजल निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगा रखा है। यह शुल्क लगाया है, ताकि इनका निर्यात कम हो और घरेलू जरूरतों को पूरी करने के लिए इनकी उपलब्धता बनी रहे। केंद्र सरकार ने अमेरिका और ईरान जंग शुरू होने के महीने भर बाद पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क एवं अवसंरचना उपकर लागू किया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल-डीजल और एटीएफ की औसत कीमतों व देश में इनकी उपलब्धता के आधार पर शुल्क की दरें तय होती हैं।

होर्मुज खुलने के बाद भी जारी रहेगा तेल संकट, चार महीने में 1.15 अरब बैरल का हुआ नुकसान

नई दिल्ली। 28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद आखिरकार सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की उम्मीदें भले ही मजबूत हो रही हैं, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए यह राहत तात्कालिक है। पिछले लगभग चार महीनों से होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद रहने के कारण दुनिया की तेल आपूर्ति को ऐसा गहरा जख्म लगा है, जिसे भरने में महीनों नहीं, बल्कि सालभर से ज्यादा का समय लगेगा।

विश्लेषकों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का साफ कहना है कि होर्मुज खुलने के बाद भी दुनिया भर के रणनीतिक और वाणिज्यिक तेल भंडार खाली ही रहेंगे, जिससे आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। कीमतों के इस ऊंचे स्तर का असर वैश्विक मांग पर भी दिखेगा। साल 2026 में वैश्विक तेल मांग में 2025 के मुकाबले 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि, 2027 में व्यापार सामान्य होने पर मांग में दोबारा 2 से 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंचे दुनिया के तेल भंडार

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के दौरान मांग को पूरा करने के लिए सरकारों ने अपने आपातकालीन भंडारों को रिकॉर्ड गति से खाली किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक, विकसित देशों के समूह (ओईसीडी) का तेल भंडार गिरकर 1990 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। संकट की शुरूआत से अब तक इस बफर स्टॉक से 163 मिलियन बैरल तेल निकाला जा चुका है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका का आपातकालीन रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व गिरकर 340.3 मिलियन बैरल पर आ गया है, जो 1983 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं ईआईए के मुताबिक, साल 2026 के अंत तक ओईसीडी देशों के पास केवल 50 दिनों की भावी मांग को पूरा करने का स्टॉक बचेगा, जो 2003 के बाद सबसे कम है।

एनालिटिक्स फर्म केप्लर और अन्य ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, फारस की खाड़ी से तेल का प्रवाह तुरंत युद्ध-पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, जिसके तीन मुख्य कारण हैं: बारूदी सुरंगें हटाने की चुनौती : युद्ध के दौरान जलमार्ग में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को पूरी तरह साफ करने और नौवहन को सुरक्षित बनाने में कई हफ्तों का समय लगेगा। लॉजिस्टिक्स और टैंकरों की कमी : बंद के दौरान वैश्विक रूट से हटाए गए खाली तेल टैंकरों को वापस फारस की खाड़ी के क्षेत्र में लाने और उनके लिए बीमा बहाल करने में समय लगेगा।

ईरान, कुवैत व यूएई की कई ऑयल रिफाइनरियों और तेल प्रतिष्ठानों को युद्ध के दौरान भारी भौतिक नुकसान पहुंचा है, जिन्हें दोबारा पूरी क्षमता से शुरू करने में महीनों लगेंगे।

कच्चे तेल में राहत से अर्थव्यवस्था को उम्मीद

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स और ईवाई जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाया है। हालांकि, घरेलू स्तर पर अल नीनो के कारण कमजोर मानसून चिंता का विषय बना हुआ है।

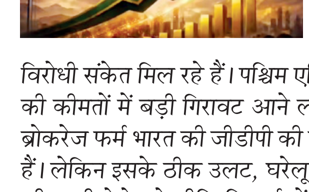

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक और घरेलू मोर्चों से परस्पर विरोधी संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम एशिया शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आने लगी है। इस राहत को देखकर वैश्विक ब्रोकरेज फर्म भारत की जीडीपी की वृद्धि के मजबूत अनुमान जारी कर रही हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, घरेलू मोर्चे पर अल नीनो के कारण मानसून की सुस्ती से देश के नीति-निमार्ताओं और अर्थशास्त्रियों की सांसें अटकी हुई हैं। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भारत का वित्त वर्ष 2026-27 का विकास अनुमान 6.1 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि चालू तिमाही की जीडीपी उम्मीद से बेहतर है। कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा भारत को मिलेगा। उधर, ईवाई ने चालू वित्त वर्ष में रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.6 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

भारत की एकता, विविधता, अखंडता और अक्षुण्णता इन्हीं राष्ट्रभक्तों की देन

सशक्त लोकतंत्र ही हमारी पहचान, हम लोकतंत्र सेनानियों का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र हित में ही सबका हित निहित है। सशक्त लोकतंत्र ही भारत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने देश को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट और सम्मानजनक पहचान दिलाई है। लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए अपना खून-पसीना बहाया, अमानवीय अत्याचार सहे और अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा हम सभी भारतवासी इन लोकतंत्र सेनानियों का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। आज देश की एकता, विविधता, अखंडता और अक्षुण्णता इन्हीं साहसी, समर्पित एवं राष्ट्रनिष्ठ कर्मवीरों की ही देन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रवीन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठिन से कठिन यातनाएं सहने वाले वीर लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जावरा, जिला रतलाम निवासी 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी श्री शांतिलाल संघवी सहित आपातकाल के दौरान प्रमुख भूमिका में रहे पूर्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता का शील्ड प्रदान कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रादेशिक सम्मेलन में आए सभी लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प-वर्षा कर उनका स्वागत-सम्मान किया। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। सम्मेलन में देश में आपातकाल पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपातकाल पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

लोकतंत्र सेनानियों के हित में की घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में लोकतंत्र सेनानियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर उन्हें तीर्थ दर्शन कराया जायेगा। इनके लिए शासकीय रेस्ट हाउस में 2 दिन तक रूकने की व्यवस्था भी की जाएगी। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर शिलालेख लिखवाये जायेंगे एवं उनके गांव, कस्बे, नगर या निवास क्षेत्र के समीप मौजूद सार्वजनिक भवनों, पार्क एवं रोड आदि का नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्चा अब सरकार उठाएगी। किसी लोकतंत्र सेनानी के बीमार पड़ने पर उन्हें उत्कृष्ट और बड़े स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र दिया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों द्वारा अपने निवास के पते पर बदलाव होने पर उन्हें दी जा रही सम्मान निधि से संबंधित बैंक या शाखा बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। किसी भी शासकीय कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों के पहुंचने पर संबंधित अधिकारी पूरे सम्मान और प्राथमिकता के साथ इनकी बात सुनेंगे तथा इनके सुझाव भी माने जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपातकाल के उस काले दौर में लोकतंत्र सेनानियों ने अनेक कष्ट सहकर मातृभूमि के मूल लोकतंत्र की रक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यदि लोकतंत्र सेनानी अपने लक्ष्य से अडिग, अटूट और दृढ़ संकल्पी न होते, तो भारत इतना मजबूत लोकतंत्र न होता। लोकतंत्र सेनानियों के अथक संघर्ष से ही हमारा लोकतंत्र सुरक्षित भी है और समृद्ध भी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आपातकाल के दौर में लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और समर्पण से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद मिलता है। हमारे आपके जैसे सामान्य परिवार के कई लोगों को भी राज्यों में जनसेवा का अवसर मिल रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमें अपने देश में लोकतंत्र की मिसाल बनाए रखना है। लोकतंत्र में जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए होना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आपातकाल के समय किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। एक प्रकार से देशभर में भय का वातावरण था। उन्होंने बताया कि उनके पिता भी 19 महीने तक जेल में रहे। तब लोकतंत्र सेनानियों पर जेलों में अनेकों अत्याचार किए गए। तत्कालीन सत्ताधीश चाहते थे कि जो लोग उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आपातकाल लगाने वाले सत्ताधीशों ने एक ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला था।

भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 है, जो अमेरिका और चीन से अधिक

पूर्व राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि मध्यप्रदेश में आज लोकतंत्र सेनानियों को 30 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने मीसाबंदियों के त्याग को समझा और दिल से उनका सम्मान समारोह कराने की शुरूआत की है। अब बंगाल के लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को प्रमाण-पत्र जारी कर कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। देशभर के लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर दर्जा मिले और उन्हें मिलने वाली 30 हजार की राशि को आयकर मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था वृद्धि के मामले में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत है, जो अमेरिका और चीन से भी अधिक है। श्री सोलंकी ने कहा कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में अनैतिकता को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने 25 जून 1975 की रात लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। हजारों स्वयं सेवकों को जेलों में डाल दिया गया। आज लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और समर्पण के कारण ही सामान्य परिवार से आने वाले डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं।

विकसित भारत के साथ विकसित मध्यप्रदेश का भी सपना होगा साकार

वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि आपातकाल के 51 वर्ष पूरे हुए हैं। ब्रिटिश शासन के दौर में देशवासियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत में भी इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने गुजरात की धरती से आपातकाल के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया था। फिर बिहार के गांधी मैदान से नारा दिया कि 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है'। तत्कालीन सत्ताधीश इससे बुरी तरह घबरा गये। आपातकाल के समय लोकतंत्र सेनानियों पर जेलों में अनेक अत्याचार किये गये। लोकतंत्र सेनानियों के त्याग के बल पर ही आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत @ 2047 का सपना देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंचेगा और विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत के साथ विकसित मध्यप्रदेश का भी सपना साकार होगा।

लोकतंत्र सेनानी का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, यह हमारा सौभाग्य है

लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में आज 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हो रहा है। प्रदेश में बीते 10 साल से लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की सुखद परंपरा चली आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पिता स्वयं लोकतंत्र सेनानी रहे। उन्होंने सेनानियों की पीड़ा को करीब से देखा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज एक लोकतंत्र सेनानी का बेटा मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री है। कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, पूर्व मंत्री एवं मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय संरक्षक श्री मेघराज जैन, लोकतंत्र सेनानी श्री अशोक पांडे, लोकतंत्र सेनानी श्री माखन सिंह चौहान, समाजसेवी श्री राहुल कोठारी, श्री रवीन्द्र यति, शिक्षाविद् श्री सुधीर अग्रवाल सहित अनेक जन प्रतिनिधि, प्रदेश भर से आए लोकतंत्र सेनानी एवं आमजन उपस्थित थे। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री संतोष कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन लोकतंत्र सेनानी श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने किया।

भारत की दूसरी आजादी के आंदोलन की तरह था आपातकाल का संघर्ष

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री कैलाश सोनी ने कहा कि आज आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। लोकतंत्र सेनानी जब मिलते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है। एक राष्ट्रीय राजनैतिक शख्सियत ने अपनी जिद के लिए लोकतंत्र को खत्म कर उनके फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नागरिकों को जेलों में डाला। तत्कालीन समय में 25 जून की रात हुए काले कारनामों को देशवासियों को स्मरण कराने के लिए 'संविधान हत्या दिवस' या 'काला दिवस' मनाने की शुरूआत की गई। आपातकाल के दौर में अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। मीडिया हाउसों पर ताले लगा दिए गए। करीब 25 से 30 बड़े पत्रकारों और संपादकों को जेलों में डाल दिया गया। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए देश में लंबा संघर्ष चला। आपातकाल का संघर्ष एक प्रकार से देश की दूसरी आजादी का आंदोलन था। सभी लोकतंत्र सेनानी लोकशाही के संवाहक हैं, संविधान के संरक्षक हैं। श्री सोनी ने कहा कि लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण देश में लोकतंत्र की मिसाल थे। कांग्रेस सरकारों ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोहों पर पाबंदियां लगाईं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनकी कोई आस्था नहीं थी। आज भारत दुनिया में खुली हवा में सांस ले पा रहा है और दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न बना। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी अनेक योजनाएं पहले की तरह संचालित हैं।

शुजालपुर अंचल को मिलेगा दो मेट्रोपॉलिटन एरिया का लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शाजापुर और शुजालपुर क्षेत्र विकास की नई मंजिलें तय करेगा। आने वाले वक्त में जहां इंदौर- उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में बड़ा भू-भाग सम्मिलित होने से इस अंचल की प्रगति तीव्र होगी, वहीं भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया से भी जुड़े होने का लाभ क्षेत्र को प्राप्त होगा। विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुजालपुर (शाजापुर) में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में आए शुजालपुर क्षेत्र के नागरिकों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर शुजालपुर क्षेत्र के नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का गणमाला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य श्री महेश केवट भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शुजालपुर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहां विधि महाविद्यालय की मंजूरी के साथ अन्य विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। प्रदेश में विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य हो रहा है। इसका लाभ शुजालपुर को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी देकर विकास की राह आसान की है। इस क्रम में आने वाले वर्षों में पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के कारण सम्पूर्ण शाजापुर जिला लाभांवित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश गेहूं के उत्पादन में और किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी के कार्य में अग्रणी है। कृषक कल्याण वर्ष में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ दुग्ध व्यवसाय के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को लाभ दिलवाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल से मंदसौर के नए हाई-वे के साथ ही शुजालपुर में हेलीपैड निर्माण और स्टेडियम निर्माण के कार्य भी किए जाएंगे। मंत्री श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थी काल से शुजालपुर क्षेत्र को अपना माना है। क्षेत्र की जनता ने विभिन्न सौगातें मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अभिनंदन का निर्णय लिया।

यूसीसी पर उच्च स्तरीय समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक

भोपाल। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। समिति का कार्य अंतिम चरण में है और आशा है कि जल्दी ही रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

भारतीय हॉकी टीम में मध्यप्रदेश का बढ़ता प्रतिनिधित्व एक उपलब्धि

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय हॉकी टीम में मध्यप्रदेश का बढ़ता प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने निवास पर भेंट के लिए आये अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी एशिया कप-2026 में पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। टूनार्मेंट का आयोजन जापान के काकामिगाहारा शहर में 29 मई से 06 जून 2026 तक किया गया था। पदक विजेता पुरूष और महिला खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर मध्यप्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सिवनी और बड़वानी के खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी बहुत साधारण परिवार से हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। निश्चित ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले एशियाई खेलों में इन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश जो कभी हॉकी में कई ओलम्पियन दे चुका हैं, कुछ वर्ष इस खेल में पीछे रहा, लेकिन अब हरियाणा जैसे राज्यों के समान अग्रणी हो रहा हैं।

खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जापान में हुए टूनार्मेंट के लिए समीर दाद जैसे कोच खिलाड़ियों को दक्ष बनाने में लगे थे। अंडर-18 की श्रेणी में 6 पुरुष खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक और 4 महिला खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक जीते हैं।

राष्ट्र सेवा ही शालिगराम जी के जीवन का था ध्येय : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्व. शालिगराम तोमर राष्ट्र सेवी थे। उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने वाले अनेक कार्यकर्ता भी तैयार किए। राष्ट्र सेवा और राष्ट्रसेवियों का निर्माण उनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। वे सामाजिक कार्यकताओं के साथ अनूठा परिवार भाव रखते थे। उनकी कार्य शैली से युवा सहज ही उनके सेवा प्रकल्पों के साथ जुड़ जाते थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मानस भवन में स्व. शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्र सेवी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। नवलय संस्था द्वारा इस वर्ष वरिष्ठ समाज सेवी श्री सदाशिव देवधर पुणे और श्री अरविंद मोघे को सम्मानित किया गया। दोनों समाज सेवियों ने विद्यार्थी परिषद, श्रमिक कल्याण, वनवासी कल्याण के साथ ही अनेक सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर कार्य किया है।

वरिष्ठ समाज सेवी श्री सदाशिव देवधर और श्री अरविंद मोघे सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. शालिगराम तोमर ने एक कक्ष के कार्यालय से संगठन से कार्य करते हुए उसे विराट रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उनके आदर्श जीवन से हजारों लाखों युवाओं ने प्रेरणा ली और सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए स्वयं को तैयार किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मानित समाज सेवियों को बधाई दी और संस्था के उद्देश्यों एवं सम्मान कार्यक्रम की सराहना की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सामाजिक कार्यकताओं के जीवन को संवारने में स्व. शालिगराम का समर्पण और सहयोग यादगार रहेगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने स्व. शालिगराम के जीवन से जुड़े संस्मरण सुनाये। सेवानिवृत्त न्यायाधीश और संगठन पदाधिकारी श्री अशोक पांडे ने कहा कि स्व. शालिगराम राष्ट्र सेवा का भाव रखते थे। राज्यसभा सदस्य श्री रजनीश अग्रवाल ने नवलय संस्था को एक प्रेरणापुंज की स्मृति में सम्मान स्थापित करने के लिए बधाई दी। महासमुंद छत्तीसगढ़ से आए डॉ. विमल चोपड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों ने सम्मान के लिए चयनित समाज सेवियों श्री देवधर और श्री मोघे को एक लाख रूपए की सम्मान निधि, शॉल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। दोनों समाजसेवियों के प्रशस्ति पत्र का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री रघुनंदन शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी श्री शशि भाई सेठ, श्री विभीषण सिंह, अनेक लोकतंत्र सेनानी, नागरिक और समाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विविधता में एकता का आधार भारत के विभिन्न राज्यों के लोग : राज्यपाल

लोक भवन में मनाया गया पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि भारत की विविधता में एकता का आधार भारत के विभिन्न राज्यों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह से मध्यप्रदेश में बंगाल के मूल निवासी घुल मिल गये हैं। हमारी अनेकता में एकता की आत्मीयता और साम्यता को राज्य स्थापना दिवस के आयोजन साकार करते है। आयोजन के मंच पर हमारी वेशभूषा, गीत, नृत्य में समाई हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता की झलक मिलती है। पश्चिम बंगाल की प्रस्तुतियों में उन्हें गुजरात के गरबा नृत्य और वेशभूषा में असम राज्य की झलक दिखाई दी।

राज्यपाल श्री पटेल आज लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के प्रसंग में आयोजित समारोह में सम्मिलित भोपालवासी बंगाली मूल के लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डा. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में भोपाल के विभिन्न कालीबाड़ियों के सदस्य उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र प्रथम की भावना को सुदृढ़, राष्ट्रीय एकात्मकता को नई शक्ति प्रदाय करने और राज्यों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक संवाद, आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने के प्रयास अद्भुत है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने गत वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल पर एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक भारत पर्व का ऐतिहासिक आयोजन कराया था। पर्व में सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक दलों और बच्चों की सहभागिता से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मंच प्रदान किया गया था। कार्यक्रम में 300 बच्चों ने कार्यक्रम में सहभागिता की थी। उन्होंने कहा कि भारत की गौरवशाली विरासत को समृद्ध बनाने में बंगाल राज्य का योगदान अतुलनीय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर विगत वर्षों से देश की युवाओं की आकांक्षाओं के अनुसार विकसित भारत निर्माण के लिए युवाओं के साथ संवाद करते हैं। लोक भवन के आयोजन में 7 से 60 साल के कलाकारों की सहभागिता और महिलाओं की बहुलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए बदलते भारत की झलक और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया।

कार्यक्रम में श्रीमती सपना गुहा ने स्वागत उद्बोधन में बंगाल की समृद्ध परम्पराओं, सांस्कृतिक विरासत के साथ ग्रामीण जन जीवन की सरलता और सांस्कृतिक छटा की रुपरेखा प्रस्तुत की सांस्कृतिक आयोजन की सूत्रधार श्रीमती महुआ चटर्जी ने ह्लहमारा बंगाल रेह्व की थीम पर बंगाल के लोकगीत, नृत्य और जन जीवन को बाउल, झूमर, धमाइल, भटयाली लोक संगीत की प्रस्तुति के द्वारा सभागार में पश्चिम बंगाल के जन जीवन को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि का स्थापना दिवस का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक वैभव और आधुनिक विकास पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अंत में मध्यप्रदेश के विकास और वैभव से परिचित कराने वाली लघु फिल्म का प्रसारण किया गया।

राज्यपाल का कार्यक्रम में बंगाली समाज के सचिव सर्वश्री सलिल चटर्जी, निलॉय घोष ने अभिनन्दन किया। आभार प्रदर्शन डा. एन. बनर्जी ने किया। संचालन सहायक सत्कार अधिकारी सुश्री सृष्टि श्रीवास्तव ने किया।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।